जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 33 संख्याः 47 प्रभात उदयपुर, गुरूवार 18 दिसम्बर, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

‘अरे दीवाने ऐसा काम न कर, राम का नाम बदनाम न कर’

शशि थरुर का लोकसभा में यह व्यंगात्मक भाषण इस बात का संकेत है कि राहुल की सोच बदल रही है, बगावती से तेवर दिखाने वाले पार्टी के नेताओं के प्रति

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- पहले राहुल की सोच होती थी, अगर पार्टी के कामकाज करने के तरीके से खुश नहीं तो पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं।
- पर, अब पार्टी द्वारा शशि थरुर को लोकसभा में खुलकर बोलने का मौका देना, इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी का रुख ''बगावती'' तेवर वाले नेताओं के प्रति कुछ नरम हुआ है।
- दूसरी ओर शशि थरुर भी कुछ सध कर बोल रहे हैं, भाजपा व प्र.मंत्री मोदी की तारीफ के पुल बांधते समय।
- शशि थरुर ने यह महसूस किया कि धीरे-धीरे भाजपा उनके चुनाव क्षेत्र, तिरुअनंतपुरम् में उनके वोट बैंक में सेंध मार रही है और यह थरुर के लिए काफी चौंकाने वाली बात थी।
- यह ही मनीष तिवाड़ी के बारे में हुआ। मनीष को लग रहा था कि पार्टी में उनको वह स्थान नहीं मिल रहा, जिसका वे अपने आपको हकदार मानते थे। पर, जब पार्टी ने उन्हें एसआईआर पर राज्यसभा में प्रथम वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और बहुत सराहा गया और कांग्रेस के लिए यह सुखद ''डवलपमैंट'' था।

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों ही मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। शशि थरूर ने सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और महात्मा गांधी नाम हटाने के निर्णय पर विरोध जताया। उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए न्यूक्लियर बिल पर भी अपनी बात रखी।

मनीष तिवारी का एसआईआर (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट) पर भाषण सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बेहद प्रभावपूर्ण हमला था, जिसमें उन्होंने सरकार की गलतियों को उजागर किया और सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता पर जोर दिया।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शशि थरूर के निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनन्तपुरम में भाजपा के प्रवेश करने से थरुर को झटका लगा है और वे थोड़े शांत पड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, थरूर की समस्या के पीछे के.सी. वेणुगोपाल हैं, जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हें बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।

इस परिदृश्य में पार्टी के भीतर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी पर शशि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ बिल पारित

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। बीमा क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रावधान करने वाले सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी।

राज्यसभा ने विधेयक पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद आज विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे मंगलवार 16 दिसंबर को ही पारित कर चुकी थी।

इस विधेयक का उद्देश्य बीमा संबंधी तीन कानूनों में संशोधन करना है। इसमें बीमा क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के अलावा कारोबार को आसान बनाने के लिए और भी कई उपाय किये गये हैं।

- राज्यसभा ने आज इसे स्वीकृति प्रदान की, लोकसभा में 16 दिसम्बर को यह बिल पारित हो चुका है।

पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि एक बीमा कंपनी का गैर-बीमा कंपनी के साथ विलय किया जा सकता है या उसे बीमा तथा गैर-बीमा कंपनियों में बांटा जा सकता है। इसके लिए बीमा नियामक से अनुमति लेनी होगी। अब पांच प्रतिशत से कम के हिस्सेदारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भारत का औद्योगिक उत्पादन घट रहा है’

राहुल गांधी जर्मनी की पाँच दिवसीय यात्रा के दौरान बी.एम.डब्ल्यु. वर्ल्ड की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- अवलोकन के दौरान, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत का औद्योगिक उत्पादन घटना दुख का विषय है, क्योंकि किसी भी देश की सफलता की कुँजी उसका औद्योगिक उत्पदान होता है।
- राहुल गांधी की जर्मनी की इस यात्रा की घोषणा लोकसभा के सत्र के दौरान की गई थी तथा इस घोषणा पर भाजपा ने कटाक्ष किया था कि राहुल गांधी के बार-बार विदेश यात्रा पर जाने से, राहुल गांधी के अपनी पार्टी कांग्रेस के प्रति समर्पण पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। जर्मनी के म्यूनिख शहर में प्रसिद्ध बीएमडब्ल्यू वर्ल्ड का गाइडेड टूर करते हुए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि किसी भी देश की सफलता के लिए उत्पादन सबसे अहम है, जबकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र गिरावट के दौर से गुजर रहा है।

समग्र आर्थिक विकास में मैन्युफैक्चरिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह देखकर अच्छा लगा कि यहां भारतीय झंडा लहरा रहा है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शोरूम का दौरा करते, वहां मौजूद लग्ज़री कारों को नजदीक से देखते और बी.एम.डब्ल्यू. वर्ल्ड घूमने आए लोगों से बातचीत करते हुए देखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि वहां 450 सीसी की एक बाइक भी है।

कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए गए वीडियो में कांग्रेस नेता ने कहा, ''भारत को उत्पादन शुरू करने की जरूरत है। किसी भी देश की सफलता की कुंजी उत्पादन होता है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है, जबकि वास्तव में इसे बढ़ना चाहिए।''

एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, ''मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग गिरावट में है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा उत्पादन करने की ज़रुरत है, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ पैदा करने की ज़रुरत है।''

राहुल गांधी दुनिया भर की 117 प्रगतिशील पार्टियों के एक प्रमुख समूह, ''प्रोग्रेसिव अलायंस'' के निमंत्रण पर जर्मनी के दौरे पर हैं।

अपने दौरे के दौरान, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे और जर्मन सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बर्लिन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जर्मनी के अपने पांच दिवसीय दौरे के दौरान, वे बुधवार को होने वाले एक बड़े आईओसी (इण्डियन ओवरसीज़ कांग्रेस) कार्यक्रम में शामिल होंगे और यूरोप भर के आईओसी नेताओं से मुलाकात करेंगे।

यह कार्यक्रम कांग्रेस की वैश्विक पहुंच और गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आईओसी के अनुसार, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से जुड़ने के लिए वहां हैं। इस दौरान एनआरआई से जुड़े मुद्दों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एच वन बी वीज़ा की फीस का सर्वाधिक असर टाटा और इंफोसिस पर पड़ेगा

अब इन कंपनियों को भारतीयों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए एक लाख डॉलर की वीज़ा फीस भरनी पड़ेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- ट्रंप के, एच वन बी वीज़ा शुल्क को एक लाख डॉलर करने के फैसले को आउट सोर्सिंग और स्टाफिंग इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा हैं। यह उद्योग एच वन बी वर्कस तलाश करने वाली कंपनियों के लिए बिचौलिए का काम करता है। इनमें टाटा कंसलटैंसी, इंफोसिस व कॉग्निज़ैंट शामिल हैं।
- अमेरिका के औद्योगिक विशेषज्ञों का मत है कि भले ही शुल्क वृद्धि को कानून की मदद से रोक दिया जाए, पर, इससे अमेरिकन वीज़ा की मांग में भारी कमी आएगी।

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। अमेरिका के बाहर से नियुक्त किए जाने वाले नए एच-1बी कर्मचारियों पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा 1,00,000 डॉलर का शुल्क तय किए जाने से आईटी आउटसोर्सिंग और स्टाफिंग उद्योग पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह उद्योग लंबे समय से दोनों राजनीतिक दलों के निशाने पर रहा है।

यह शुल्क ट्रंप प्रशासन द्वारा अब तक कुशल विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगाई गई सबसे बड़ी पाबंदी है।

इसका असमान रूप से ज्यादा असर उन बहुराष्ट्रीय स्टाफिंग कंपनियों पर पड़ेगा, जो एच-1बी कर्मचारियों की तलाश कर रहीं कंपनियों के लिए बिचौलिये की भूमिका निभाती हैं। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड और कॉग्निज़ेंट टैक्नॉलजी सॉल्यूशंस कॉर्प शामिल हैं।

मई 2020 से मई 2024 के बीच टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस और कॉग्निज़ेंट टैक्नॉलजी सॉल्यूशंस में की गईं लगभग 90 प्रतिशत नई एच-1बी नियुक्तियों को अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों से मंजूरी मिली थी।

ब्लूमबर्ग के विश्लेषण के अनुसार, इसी अवधि में इंफोसिस की 93 प्रतिशत से अधिक नई एच-1बी नियुक्तियों, जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिले भागवत

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने बुधवार को उपराष्ट्रपति सीपी

- उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के अधिकारिक एक्स हैंडल से इस मुलाकात की जानकारी दी गई और बताया गया कि सरसंघ चालक भागवत ने उनसे सांस्कृतिक व शैक्षिक मसलों पर चर्चा की।

राधाकृष्णन से उपराष्ट्रपति एनक्लेव में मुलाकात की। इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट के माध्यम से की गई।

सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति और सरसंघ चालक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हम सैवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर राज्य) को भारत से अलग करने में मदद देंगे’

बाँग्लादेश के एक नेता के इस बयान पर नाराज़ केन्द्र सरकार ने बाँग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- बाँग्लादेश की नैशनल सिटिज़न पार्टी के एक नेता ने धमकी दी है कि ढाका, भारत विरोधी ताकतों को शरण देगा और ''सैवन सिस्टर्स'' अर्थात् सात पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने में मदद करेगा।
- भारत में बाँग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर उन्हें बाँग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाँग्लादेश के नेताओं की भारत विरोधी टिप्पणी पर भारत सरकार की नाराज़गी से अवगत कराया गया।

नई दिल्ली, 17 दिसंबर। ढाका में भारतीय उच्चायोग को दी गई धमकियों और बाँग्लादेशी राजनीतिक नेताओं के भारत विरोधी भड़काऊ बयानों पर औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ज करने के लिए, भारत ने दिल्ली में मौजूद बाँग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज़ हमीदुल्लाह को तलब किया है।

यह सम्मन बाँग्लादेश की नैशनल सिटीज़न पार्टी (एनसीपी) के एक नेता द्वारा दी गई उस धमकी के बाद भेजा गया है, जिसमें कहा गया था कि ढाका, भारत विरोधी ताकतों को शरण देगा और ''सेवन सिस्टर्स'', जो कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों को संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, को भारत से अलग करने में मदद करेगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमीदुल्लाह को बाँग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया गया।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, उनका बयान, ''विशेष रूप से, उन चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर खींचा गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आस-पास ''सुरक्षा के लिए खतरा'' पैदा करने के लिए योजनाओं की घोषणा की है।

भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह बाँग्लादेश में हाल की घटनाओं के संदर्भ में चरमपंथी तत्वों द्वारा बनाए गए झूठे कथानक को पूरी तरह से नकारता है।

मंत्रालय ने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो मामले की पूरी जांच की है और न इन घटनाओं के संबंध में भारत के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रमाण साझा किए हैं।''

बयान में कहा गया, ''भारत के बाँग्लादेश के लोगों के साथ गहरे और दोस्ताना रिश्ते हैं, जिनकी जड़ें मुक्ति संग्राम में निहित हैं और ये रिश्ते विभिन्न विकासात्मक तथा दोनों देशों की जनता की पहल से मजबूत हुए हैं। हम बाँग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं और हमने लगातार स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों की अपील की है, जो शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिम सरकार अपने कूटनीतिक दायित्वों के तहत, बाँग्लादेश में मिशनों और पोस्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।''

''सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करे देंगे'', छात्रों की पार्टी नैशनल सिटीज़न पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख हसनात अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की। उन्होंने इंकलाब मंच द्वारा आयोजित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में 50 प्रतिशत कर्मचारी ''वर्क फ्रॉम होम'' करेंगे

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिये गुरुवार (18 दिसंबर) से 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम सुनिश्चित करने के लिये दिशा निर्देश जारी किये।

- दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा 18 दिसम्बर से यह आदेश सभी सरकारी व निजी संस्थानों पर लागू होगा।

मिश्रा ने कहा कि ये निर्देश अस्पतालों, अग्निशमन सेवा, जेल प्रशासन, निजी परिवहन, बिजली और पानी विभागों, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण विभाग सहित, ज़रूरी सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। दिशा-निर्देशों में यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ नैशनल हैरल्ड मुकदमे से पीछे हटने को तैयार नहीं है भाजपा

भाजपा के प्रवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय ने तकनीकी कारणों के आधार पर ई.डी. को मनी लॉण्डरिंग एक्ट के तहत राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ जाँच की कार्यवाही पर रोक लगाई है

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- प्रवक्ताओं का यह भी कहना है कि न्यायालय का निर्णय, राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ लगे आरोपों की सच्चाई व गुणवत्ता में कमी के कारण नहीं लिया गया है।
- अतः, यह कहना पूर्ण सच नहीं है कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी को ''रिलीफ'' (रियायत) मिली है, न्यायालय से।
- दूसरी ओर, कांग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक रूप से मीडियाकर्मियों के समक्ष कहा कि न्यायालय का निर्णय, प्र.मंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के मुँह पर चपत है तथा दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

नई दिल्ली, 17 दिसंबर। सत्तारूढ़ भाजपा को न्यायपालिका से भी नकारात्मक निर्णय स्वीकार करने की आदत नहीं, इसलिए वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ लंबे समय से चल रहे नेशनल हैरल्ड मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है।

सरकारी सूत्रों ने बताया, असल में एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) को कोर्ट के आदेश पर स्टे मिलने की संभावना है और उसे नेशनल हैरल्ड की जब्त की गई करोड़ों की संपत्ति को वापस नहीं करना पड़ेगा।

भाजपा के नेताओं ने, नाम न बताने की शर्त पर, कहा कि हमें इस मामले को लगातार आगे बढ़ाना होगा और हर कानूनी विकल्प का पता लगाना होगा, क्योंकि यह मामला हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, और वह है गांधी परिवार को दबाव में रखना।

दिल्ली की एक अदालत ने एक दिन पहले ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था, और इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा-नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक रुख तेज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ''मुंह पर तमाचा'' करार दिया।

खड़गे ने मीडिया से कहा, ''यह मामला एक राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम था। इसे गांधी परिवार को परेशान करने के लिए तैयार किया गया था। इस निर्णय के बाद मोदी और शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह उनके मुंह पर तमाचा है, सत्य की जीत हुई है।''

भाजपा ने इसके जवाब में अपनी हमलावर रणनीति को तेज किया, पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार पर ''राजनीति में सबसे भ्रष्ट परिवार होने'' का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 2,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी, और उन्होंने कांग्रेस के ''राजनीतिक प्रतिशोध'' के दावों को खारिज किया।

भाटिया ने खड़गे पर आरोप लगाया कि ''वे अदालत के निर्णय को क्लीन चिट के रूप में प्रस्तुत करके जनता को गुमराह कर रहे हैं,'' और यह तर्क दिया कि यह आदेश कानूनी और तकनीकी आधार पर था, न कि आरोपों की सच्चाई पर। उन्होंने कहा, ''अगर कोई राजनीति में सबसे भ्रष्ट है, तो वह गांधी परिवार है,'' अदालतों में कई बार जाने के बावजूद गांधी परिवार को कोई कानूनी राहत नहीं मिली।

भाजपा नेता के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही बिना पंजीकृत एफआईआर के नहीं चल सकती, लेकिन इस आधार पर अन्य एजेंसियों को अपनी जांच जारी रखनी थी।

इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हैरल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट की संज्ञान लेने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि पीएमएलए की कार्यवाही इस आधार पर मान्य नहीं है, क्योंकि यह मामला सुब्रमण्यम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओमान के सुल्तान ने हवाई अड्डे पर किया मोदी का स्वागत

मस्कट, 17 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की चार दिन की यात्रा के अंतिम पड़ाव में बुधवार शाम यहां मस्कट पहुंच गए, जहां हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने हवाई अड्डे पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।

- प्र.मंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे।

मोदी ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। उनके स्वागत के दौरान भारतीय राष्ट्रीय गान की धुन बजाई गई।

प्रधानमंत्री ने मस्कट पहुंचते ही ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद के साथ बैठक की।

विचार बिन्दु

समस्त महान गलतियों की तह में अभिमान ही होता है। –रस्किन

राज के दो साल : भजनलाल सरकार के विश्वास और विकास का लेखा-जोखा

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार को दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को अपने जन्मदिन के दिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप मे शपथ ली थी। राज्य सरकार दो वर्षों में अर्जित अपनी उपलब्धियों को 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे 15 दिनों तक जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। राज्य सरकार के कार्यों की दो साल की उपलब्धियों की बात करे तो भजनलाल शर्मा राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने सरपंच से मुख्यमंत्री के पद की यात्रा का सफर सफलतापूर्वक तय किया है। निश्चय ही ग्राम पंचायत के सरपंच से मुख्यमंत्री बनने तक का भजनलाल शर्मा का सफर रोचक और प्रेरणादायी कहा जा सकता है। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसम्बर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए यह संकल्प लिया था कि राज्य सरकार प्रदेश की 36 कौमों के विकास के लिए वचनबद्धता के साथ कार्य कर प्रदेश में प्रगति और विकास की नई शुरूआत करेगी। उन्होंने यह संकल्प भी लिया कि विकास सभी के साथ और सबकी भागीदारी से ही होगा। सभी लोग एक साथ चलेंगे तो बदलाव आयेगा और राजस्थान प्रगति के नये सोपान तय करेगा। राजस्थान में भाजपा संगठन से जुड़े एक साधारण कार्यकर्त्ता और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपकर मोदी और अमित शाह ने समूचे देश को चौंका दिया था। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए अनेक बड़े दावेदारों के नाम सामने आये थे, मगर मोदी ने संगठन से जुड़े एक कार्यकर्त्ता को मुख्यमंत्री का ताज सौंपकर पूरे देश में यह सन्देश दे दिया कि भाजपा में जमीनी कार्यकर्त्ता भी सर्वोच्च पद पर पहुँच सकता है।

उपलब्धियों का जश्न

हर सरकार अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाती आई है। इसी क्रम में भजन लाल सरकार भी अपनी जन हितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ अपना विज़न लोगों के सामने रख रही है। सरकार का दावा है कि 2 साल में सरकार लगातार जनता के बीच गई और जन हितैषी कार्यों को अमलीजामा पहनाया। इस अवधि में भजनलाल सरकार के किसी भी मंत्री के दामन पर कोई दाग नहीं लगा, हालांकि अधिकारियों की कार्यशैली पर अवश्य सवालिया निशान लगे। दो वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता दी है। भजनलाल सरकार का दावा है कि 2 साल में ही जनता की सरकार के रूप में संवेदनशीलता से किये कार्य का परिणाम है कि आज समाज के सभी वर्ग सरकार के कार्यों से बेहद संतुष्ट है। सरकार का दावा है कि इस अवधि में सरकार लगातार जनता के बीच गई और जनकल्याणकारी कार्यों को अमलीजामा पहनाया। राज्य मंत्रीपरिषद के सदस्य प्रदेशभर में भ्रमण कर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे है।

आंकड़े सच बोलते है

यह दावा भी किया जा रहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के पांच सालों की अपेक्षा भजनलाल सरकार के दो सालों में अधिक बेहतर कार्य किये है। इसे 5 साल बनाम 2 साल के आंकड़े सच बोलते है के शीर्षक के माध्यम से प्रदर्शित किये जा रहे है। इन आंकड़ों में विशेष रूप से नहरी तंत्र से सृजित सिचाई सुविधा, फार्म पोंड, ओडीएफ प्लस गांव, निर्मित सड़कों की लम्बाई, सड़कों से जोड़े गए गांव, बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि, स्कूली छात्रों को टैबलेट/ लेपटॉप वितरण छात्राओं को स्कूटी वितरण, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना, महाविद्यालयों के भवन निर्माण, नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन, सेटेलाइट अस्पताल स्थापना,कौशल प्रशिक्षण और गौशालाओं को सहायता की उपलब्धियों को प्रदर्शित कर दावा किया गया है कि हमारी सरकार ने दो सालों में ही पांच सालों को पछाड़ दिया। उपलब्धियों के इन आंकड़ों को देश भर में समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है।

मुख्यमंत्री की सोच है कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए सरकार और आमजन के बीच आपसी संवाद को और आसान कैसे बनाया जाये, इसके लिए अधिक तत्परता व सजगता से काम करना होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुशासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इन मूलभूत सुविधाओं व आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास के सभी को एक जुट होकर प्रयास करने की जरुरत है तभी मुस्कराते राजस्थान का हमारा सपना साकार होगा।

मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल में जनसेवा की अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास और आधारभूत ढांचे को जन आंकाक्षाओं के अनुरूप मजबूत बनाने में जुटे हैं। भजनलाल सरकार महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं, व्यापारियों और दिव्यांग जनों सहित हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इस दौरान 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं और 500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ-साथ आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। जनता से सीधे जुड़े विभागों ऊर्जा उत्पादन, सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल, जल संसाधन, नगरीय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास कार्य किये। सरकार का दावा है कि हम जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के विकास का पहिया बिना रुके, बिना थमे आगे बढ़ रहा है। चुनाव के समय जनता से किए गए 392 संकल्पों में से 274 या तो पूरे किए जा चुके हैं या प्रगति पर हैं। प्रदेश ने पिछले दो वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। साथ ही मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और विकास के संकेतकों में भी सकारात्मक सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री की सोच है कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए सरकार और आमजन के बीच आपसी संवाद को और आसान कैसे बनाया जाये, इसके लिए अधिक तत्परता व सजगता से काम करना होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुशासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इन मूलभूत सुविधाओं व आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास के सभी को एक जुट होकर प्रयास करने की जरुरत है तभी मुस्कराते राजस्थान का हमारा सपना साकार होगा। आमजन से जो काम पांच साल में पूरे करने का वादा किया था, उनमें से 70 प्रतिशत कार्य दो वर्ष में ही कर चुके हैं। दो वर्षों की बजट घोषणाओं में से 73 प्रतिशत घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी है या प्रगतिरत हैं। सरकार के दावे के विपरीत विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया जिससे हर वर्ग दुखी और परेशान है। कानून व्यवथा छिन्न-भिन्न है। रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। आमजन बेहाल है ऐसे में खुशहाली की बात करना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना है। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार घोषित किया मगर इसी पर्ची सरकार ने दो साल में राजस्थान को अग्रिम पंक्ति का राज्य बनाने के लिए न केवल नीतिगत सुधारों की पहल की अपितु आम नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समर्पित भाव से प्रयास किए हैं।

साफ़ सुथरी छवि और ईमानदार नेता

मुख्यमंत्री भजनलाल की छवि एक साफ़-सुथरे, मेहनती, समर्पित और ईमानदार नेता की है। जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ प्रदेश के विकास में जुटे है। आम आदमी की सोच है प्रदेश के बहुमुखी विकास में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और कुशासन प्रगति और विकास के दुश्मन के रूप में उभरे है। जब तक इन पर काबू नहीं पाया जायेगा तब तक विकास और प्रगति एकांगी होगी। हर सरकार लोक कल्याण का वादा करती है मगर लोक कल्याण के मार्ग में अवरोध बने इन कारकों को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस कारवाही नहीं करती। चूँकि राजनेताओं के हित इनसे जुड़े है इसलिए इन बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक समाज से यह बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, हम भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगते रहेंगे। भ्रष्टाचार आज भी समाज को खोखला कर रहा है। इस बेतरणी में सभी अपने हाथ धोना चाहते है। ऐसा लगता है राजस्थान में भ्रष्ट कर्मियों से अपना नापाक गठजोड़ स्थापित कर लिया है।जन प्रतिनिधियों और सरकारी कारिंदों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार और पद के दुरूपयोग के प्रकरणों का खुलासा आये दिन मीडिया में सुर्खियों में पढ़ने को मिल जाता है। जनता के खून पसीने की कमाई को हड़प करने का जरिया भ्रष्टाचारियों ने अपना लिया है। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार ने अपना दामन चहुंओर फैला रखा है। राजस्व, तहसील, कलेक्ट्रेट, जेडीए, स्थानीय निकाय, सिंचाई, जलदाय, रसद, सड़क, पंजीयन जैसे दर्जनों कार्यालय हैं जहां बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता। जब तक मुट्ठी गर्म न की जाए तब तक कोई काम ही नहीं होता। भ्रष्टाचार एक संचारी बीमारी की भांति इतनी तेजी से फैल रहा है कि लोगों को अपना भविष्य अंधकार से भरा नजर आने लगा है। वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करना चाहते है। ऐसे में प्रदेशवासियों की आकांक्षा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल अपनी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर जनता को राहत प्रदान करे।

–अतिथि संपादक,
बालमुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

सेवा शिविर: सुशासन की अवधारणा को नई दिशा

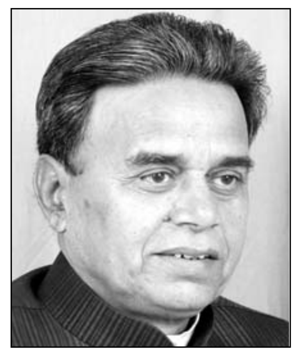
जोगाराम पटेल

राज्य के शासन-प्रशासन का वास्तविक मूल्यांकन उसकी नितियों और निर्णय से आम नागरिक के जीवन में मिलने वाली प्रत्यक्ष राहत और सुविधाओं से किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सेवा शिविर इस कसौटी पर खरे उतरते दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई यह पहल केवल एक प्रशासनिक गतिविधि नहीं, बल्कि सुशासन को जमीन पर उतारने का सशक्त माध्यम है। यहां सरकार दफ्तरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर स्वयं जनता के द्वार तक पहुंच रही है।

सेवा शिविरों का उद्देश्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक शासन और सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करना है। वर्षों से यह शिकायत रही कि सरकारी योजनाएं और सेवाएं फाइलों, प्रक्रियाओं और दफ्तरों के बीच उलझकर रह जाती हैं। सेवा शिविरों ने इस मानसिकता को तोड़ा है। यह एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जहां प्रशासन, योजनाएं और समाधान एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। यह बदलाव अपने आप में सुशासन की परिभाषा को नया आयाम देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इन शिविरों की शुरुआत की गई। इससे यह अभियान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की व्यापक राष्ट्रीय सोच से जुड़ गया। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक निरंतरता का संकेत है, जहां केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर शासन का लक्ष्य अंत्योदय है।

सेवा शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां 18 विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले जिस कार्य के लिए आम नागरिक को कई विभागों और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वही काम अब शिविर स्थल पर कुछ ही घंटों में पूरा हो रहा है। नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार, भू-राजस्व शुद्धिकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली-पानी से जुड़ी शिकायतें आदि सभी सेवाएं अब कतार, फाइल और देरी से मुक्त होकर त्वरित समाधान का रूप ले चुकी हैं।

अब तक 2 लाख से अधिक जाति प्रमाण पत्र, 1.72 लाख मूल निवास प्रमाण पत्र, 1.53 लाख भू-राजस्व शुद्धिकरण प्रकरण और 1.24 लाख नामांतरण मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। ये आंकड़े आम नागरिक के समय, श्रम और सम्मान की बचत का प्रमाण हैं।

ग्रामीण सेवा शिविर: पंचायत स्तर पर सुशासन

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को दो ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी गांव छूटे नहीं। राजस्व विभाग मौके पर ही नामांतरण, नोटिस तामील और प्रमाण पत्र वितरण कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल सर्वे कर रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग टीबी मुक्त भारत, मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच और एनीमिया परीक्षण जैसी योजनाओं को धरातल पर उतार रहा है।

पशुपालन विभाग द्वारा अब तक 2.60 लाख से अधिक मवेशी बीमा पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालकों के लिए बड़ी सुरक्षा है। कृषि विभाग बीज किट वितरण के माध्यम से किसानों को राहत दे रहा है, जबकि आपदा प्रबंधन विभाग मौके पर ही राहत राशि स्वीकृत कर रहा है। यह सब मिलकर ग्रामीण सुशासन का नया मॉडल प्रस्तुत करता है।

शहरी सेवा शिविर: सुविधा के साथ सौंदर्य

शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर केवल प्रमाण पत्र और आवेदन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहरी ढांचे में प्रत्यक्ष सुधार का माध्यम भी बन रहे हैं। सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और नई लाइट्स की स्थापना जैसे कार्य शिविरों के साथ-साथ किए जा रहे हैं।

नगर निकायों में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टों का निस्तारण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आवेदन आदि कार्य भी इन्हीं शिविरों में किए रहे हैं। अब तक 1.95 लाख से अधिक पट्टों का वितरण, 1.42 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, 1.98 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रकरणों का निस्तारण और 1.48 लाख जनधन खातों का संचालन किया जा चुका है। यह दर्शाता है कि शहरी सेवा शिविर प्रशासनिक सुविधा के साथ-साथ जीवन गुणवत्ता सुधार का भी माध्यम बन चुके हैं।

सेवा शिविरों का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है। शिविरों के माध्यम से 24.36 लाख मरीजों का उपचार, 10.77 लाख लोगों की टीबी व एनसीडी स्क्रीनिंग और 17 लाख किशोरियों व गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच की जा चुकी है।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर 95,800 से अधिक आवेदन स्वीकृत, जन आधार योजना में 1.13 लाख लाभार्थी, 25 हजार स्वनिधि ऋण और 75,600 वय वंदन कार्ड जारी होना इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक सुरक्षा अब कागजों तक सीमित नहीं रही। इन शिविरों का सबसे बड़ा प्रभाव जन विश्वास की पुनर्स्थापना के रूप में सामने आया है। वर्षों से लंबित नामांतरण, प्रमाण पत्र या बिजली बिल से जुड़ी समस्याएं अब कुछ घंटों में सुलझ रही हैं। इससे न केवल जनता का सरकार पर भरोसा बढ़ा है, बल्कि प्रशासनिक इकाइयों की कार्यकुशलता और जवाबदेही भी मजबूत हुई है।

नगरीय निकायों में दी गई विशेष रियायतें जैसे बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी से हजारों परिवारों और व्यापारियों के लिए सीधी राहत हैं। यह दिखाता है कि सरकार नियमों के साथ-साथ संवेदनशीलता को भी उतना ही महत्व दे रही है।

सेवा शिविर आज पारदर्शिता, सरलता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता का संयुक्त उदाहरण बन चुके हैं। घोषणाओं के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन की सतत निगरानी और मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि यह पहल केवल आयोजन न बनकर रह जाए, बल्कि स्थायी प्रशासनिक सुधार का माध्यम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह सोच कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी शासन का केंद्र हो, सेवा शिविरों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है। यह पहल बताती है कि जब राजनीतिक संकल्प और प्रशासनिक इच्छाशक्ति एक दिशा में काम करें, तो सुशासन केवल नारा नहीं, बल्कि जन-जीवन का अनुभव बन जाता है। सेवा शिविर वास्तव में यह संदेश दे रहे हैं कि सरकार अब दरवाजे पर दस्तक देने वाली संस्था बन चुकी है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है।

–जोगाराम पटेल,
संसदीय कार्य, विधि एवं न्यायिक कार्य मंत्री

महाभियोग को बनाया दबाव बनाने और प्रतिशोध का एक साधन

सूर्यप्रतापसिंह राजावत

आज भारत राजनीति में गिरावट, राजनीतिक पार्टियों में संवैधानिक नैतिकता के पतन और भारत के लोगों के प्रतिनिधियों के पतन का गवाह बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किए बिना 100 सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना, भारत के संविधान में अविश्वास, न्यायपालिका में भरोसे की कमी और लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ, न्यायपालिका को धमकाने और प्रतिशोध लेने का एक हथियार बनाया है।

यह मामला अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के प्रबंधन और दरगाह प्रबंधन समिति के बीच है। मूल रूप से यह मुद्दा संपत्ति जो कि थिरुप्परंकुंद्रण पहाड़ी पर स्थित है पर नागरिक अधिकारों से संबंधित है, जिस पर 1923 में ही प्रिवी काउंसिल द्वारा घोषणा और निषेधाज्ञा का मुकदमा निर्णितहोगयाथा । मद्रास उच्च न्यायालय ने1996 के आदेश में मुस्लिम समुदाय की सीमांकित भूमि से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर दीपक जलाने की अनुमति दी गई है। 2005 में शांति समिति के प्रस्ताव में भी इसे मान्यता दी गई थी। चूंकि यह मुद्दा अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के प्रबंधन और दरगाह प्रबंधन समिति के बीच है, इसलिए जो एक पक्ष के लिए पवित्र और पावन है, वह दूसरे पक्ष के लिए समान नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2025 में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से दरगाह में पशु बलि के प्रयास पर रोक लगा दी गई थी।

याचिका में बताई गई घटनाओं का क्रम, भारत में आपसी भाईचारे के लिए कुछ बातें एकदम साफ़ कर देता है कि दोनों समुदायों को शांति से साथ चाहिए, लेकिन नागरिक अधिकारों की कुर्बानी की कीमत पर नहीं। संवैधानिक नैतिकता के दायरे में सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर रीति-रिवाजों और परंपराओं से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल है, वह है भक्तों की भूमिका और कर्तव्य, जहाँ धार्मिक संस्था के ट्रस्टी वैध पारंपरिक प्रथाओं को निभाने और संरक्षित करने में विफल रहते हैं। यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मंदिर के प्रबंधन को निर्देश देने के लिए दायर की गई थी कि वे दीपाथून नामक पत्थर के मंदिर के खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाएँ जोकि दरगाह से 50 मीटर दूर स्थित है और न्यायिक आदेश की अनुमति से तीन गुना दूर है। याचिकाकर्ता ने मंदिर प्रबंधन के कार्तिगई दीपम को अलग जगह पर जलाने के निर्देशों को चुनौती दी। याचिकाकर्ता की प्रार्थना को लोकस स्टैंडी, रेस ज्यूडिकाटा, पूजा स्थल अधिनियम जैसी आपत्तियों पर सम्पूर्ण विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन/देवस्थानम को निर्देश दिया कि वे सामान्य स्थानों के अलावा दीपाथून पर भी कार्तिगई दीपम जलाएँ और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन कोर्ट के निर्देशों का पालन केवल अवमानना याचिका दायर करने और कोर्ट द्वारा सीआईएसएफ कर्मियों की टीम को याचिकाकर्ता और उसके दस साथियों को सुरक्षा प्रदान करने और कोर्ट के आदेश को लागू करने के निर्देश देने के बाद ही किया गया।यह बताना ज़रूरी है कि दरगाह कमेटी ने उस आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की है जिसे लागू किया जाना है। राज्य सरकार ने विवादित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। भक्त याचिकाकर्ता ने खुद दीपक जलाने का दावा नहीं किया था, बल्कि वह चाहता था कि मंदिर ट्रस्ट उन परंपराओं को बनाए रखे जो प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हैं। जब मंदिर ट्रस्ट ने आदेशों का पालन नहीं किया, तब सांप्रदायिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए केवल दस लोगों को दीपक जलाने की अनुमति दी गई, जो दरगाह से तयशुदा दूरी से तीन गुणा दूरी पर है। घटनाओं को देखते हुए कई सवाल खड़े होते हैं, यह भारत के संविधान की योजना, आलोच्य आदेश के खिलाफ लंबित अपील, साथ ही हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य अन्तोगत्वा, केंद्र सरकार की सीआईएसएफ एजेंसी ने आदेश का पालन करवाया, जिससे कानून के शासन को बनाए रखा गया।

तमिलनाडु राज्य का यह अवज्ञापूर्ण कार्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए ली गई शपथ के अक्षर और भावना का उल्लंघन है। यह इस बात पर भी ज़ोर देता है कि राज्य का नौकरशाही तंत्र न्यायपालिका के कानूनी आदेशों और उच्च अधिकारी के अवैध आदेशों और उनके परिणामों के बीच अंतर को समझने में विफल रहा। यह संविधान के प्रति अनादर और राजनीतिक दलों की हताशा को दर्शाता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मेंलंबित आदेश पर अंतिम फैसले का इंतजार किए बिना महाभियोग प्रस्ताव का विकल्प चुना। निष्कर्ष के तौर पर, यह देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है जहाँ एक राजनीतिक विचारधारा संवैधानिक अदालत द्वारा न्यायिक फैसले पर असंतोष व्यक्त करती है, उस जज पर दुराचार और अक्षमता का आरोप लगाया जो भारत के संविधान के दायरे में फैसला सुनाता है। यह कहना कि यह विवाद धार्मिक प्रकृति का है, गुमराह करने वाला है। इसका इस्तेमाल मीडिया में अफवाहें फैलाने और वोट बैंक को खुश करने के लिए एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग प्रस्ताव पर संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र का उल्लंघन है।

सूर्यप्रतापसिंह राजावत
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

जाटोली गांव में घटिया सीसी सड़क निर्माण से जलभराव, ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया, घरों में घुसता है बारिश का पानी

अलवर, (निसं)। जाटोली में नवनिर्मित सीसी सड़क में अनियमितताओं के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़क की अत्यधिक ऊंचाई और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से बारिश का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया है, जिससे आवागमन भी बाधित हुआ है।

- **आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्मित सड़क की डिज़ाइन व गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है**
- **ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की**

गांव निवासी राकेश कुमार गौतम ने बताया कि ठेकेदार द्वारा निर्मित सड़क की डिज़ाइन और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। सड़क की अधिक ऊंचाई के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे घरों में पानी भर रहा है और ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से स्कूली बच्चों, पैदल राहगीरों और बुजुर्गों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, जिसमें निर्धारित मानकों और शर्तों की अनदेखी की गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी सड़क निर्माण परियोजनाओं में जल निकासी, ऊंचाई और गुणवत्ता संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश होते हैं। हालांकि, ठेकेदार ने कथित तौर पर निजी लाभ के लिए इन शर्तों की अनदेखी की, जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर जाटोली गांव में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सड़क निर्माण को दोबारा सही मानकों के अनुसार कराने की भी अपील की है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 18 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 8:07 तक, धृति योग दिन 3:06 तक, विष्टि करण दिन 3:46 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 8:07 तक है। भद्रा दिन 3:46 तक रहेगी। आज मास शिवरात्रि, श्री जय प्रभु विजय पुण्य त्रिस्तुतिक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:31 तक, चर 11:06 से 12:23 तक, लाभ-अमृत 12:23 से 2:58 तक, शुभ 4:15 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 5:32 तक

मेष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

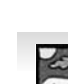
वृष
परिवार में आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

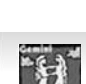
मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कन्या
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

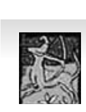
धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-गृहस्थी के खर्चों पर नियंत्रण बढ़ेगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

फिजियोथेरेपी चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया

उदयपुर, (कासं)। आज पूरे विश्व में एलोपेथी चिकित्सा में अनेक प्रकार के साईड इफेक्ट होने से मरीज फिजियोथेरेपी चिकित्सा को अपनाने लगे है, इसमें किसी प्रकार का कोई साईड इफेक्ट भी नहीं है व्यक्ति अपने घरों में बैठकर इस विधा के द्वारा अपने आप को ठीक कर सकता है। इसमें कई प्रकार के नवीन आयाम भी जुड़े है जो फिजियोथेरिपस्ट की सलाह से इसके अपना सकते है।

उक्त विचार राजस्थान विद्यापीठ संघटक फिजियोथेरेपी चिकित्सा महाविद्यालय के 25 वर्ष पूर्ण होने पर

- **खेलों में चोट व हडिड्यों के विकार में टेपिंग थेरेपी पर अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन**

आयोजित दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशॉप के शुभारंभ के अवसर पर कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। प्रो. सारंगदेवोत ने कहा कि हर बिमारी में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका बढी है, विद्यार्थियों को आधुनिक फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धतीयों का उपयोग कर अधिक से अधिक बीमारियों के उपचार करने पर बल दिया। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉ. शैलेन्द्र मेहता ने दो दिवसीय सेमीनार की जानकारी दी। डॉ. मेहता ने बताया कि सेमीनार में देश विदेश के 300 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे है। अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर ने कहा कि प्राचीन समय से योग के माध्यम से इस विधा को अपनाते रहे है इसमें समय के साथ नवाचार का जोडा गया है। मुख्य वक्ता के रूप में वर्कशॉप में इटली से आये हुये विषय विशेषज्ञ प्रो. बेलिया रोजारियो द्वारा विद्यार्थियों को टेपिंग, मेकेनिक टुल की मदद से शरीर के सोफ्ट टीशु व मांसपेशियों का मोबलाईजेशन पद्वति का लाईव डेमों के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया। इसमें विभिन्न बीमारियों जैसे जलना, खेल की चोटें, कंधे की चोट, फैक्चर, गर्दन का दर्द, घुटने का दर्द, कोहनी का दर्द जैसी विभिन्न समस्याओं के उपचार की जानकारी दी। संचालन डॉ. डॉ. प्रज्ञा भट्ट ने किया। आभार डॉ॰ सुमिता खाउण्ड ने जताया। इस अवसर पर डॉ॰ सुमिता खाउण्ड डॉ. विनोद नायर, डॉ. मानश क्रांति, डॉ. रोनिता सोनी, डॉ. चिराग पुर्बिया सहित विद्यार्थी उपस्थित थे।

फिजियोथेरेपी चिकित्सा महाविद्यालय का 25वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया।

श्री पीताम्बरा आश्रम में पर्यावरण चेतना संगोष्ठी आज

बांसवाड़ा, जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति बहुआयामी जागरूकता संचार के विभिन्न आयामों पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए नटवरानन्दी वेलफेयर फाउण्डेशन एवं गायत्री मण्डल के संयुक्त तत्वावधान में आज गुरुवार रात्रि 8 बजे शहर के श्री वनेश्वर महादेव के समीप अवस्थित श्री पीताम्बरा आश्रम में पर्यावरण चेतना संगोष्ठी होगी। बड़ा रामद्वारा के संत रामप्रकाश रामस्नेही महाराज के सानिध्य में आयोजित संगोष्ठी में जल संरक्षण और प्लास्टिक रीयूज पर चर्चा की जाएगी। पर्यावरण चेतना विशेषज्ञ संदीप सोनी मुख्य वक्ता के रूप में पर्यावरण संरक्षण संबंधित व्याख्यान देंगे। शहर के प्रबुद्धजन, पर्यावरणविद् एवं लोकमान्य नागरिक मिलकर व्यापक विचार-विमर्श और सुझावों के उपरान्त इनसे संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए ठोस एवं प्रभावी रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे।

एडवांस्ड डेंटल इम्प्लांटोलॉजी पर दो दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन

उदयपुर,। पेसिफिक डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (पीडीसीआरसी) में जर्मनी, इज़राइल, तुर्क़ी, दुबई और प्रदेश के 50 से ज्यादा डेंटल सर्जनों के लिए एडवांस्ड डेंटल इम्प्लांटोलॉजी पर दो दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेंटल सर्जनों को नवीनतम तकनीकों और ज्ञान का आदान-प्रदान करने का बेहतरीन मंच प्रदान किया।

कार्यक्रम के इस विशेष अवसर पर पीएमयू के चेयरपर्सन राहुल अठावाल, पीएमसीएच की चेयरपर्सन प्रीति अठावाल और ऐक्जिक्यूटिव डॉयरेक्टर अमन अठावाल ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने इस आयोजन के महत्व को बताते हुए डेंटल सर्जनों के बीच ज्ञान साझा करने और चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को चिकित्सा और

- **जर्मनी, इज़राइल, तुर्क़ी और दुबई सहित प्रदेश के**
- **50 से ज्यादा डेंटल सर्जनों ने की शिरकत**

शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यशाला के मुख्य क्लिनिकल मेंटर और पीडीसीआरसी के प्रिंसिपल डॉ.गौरव भारद्वाज ने बताया कि इस वर्कशॉप में विभिन्न देशों से आए विशेषज्ञों ने डेंटल इम्प्लांट्स की उन्नत तकनीकों और प्रक्रियाओं पर विचार-विमर्श किया और अपने अनुभव साझा किए। इससे स्थानीय डेंटल सर्जनों को नई जानकारी प्राप्त हुई और उनके कौशल में वृद्धि हुई। इस वर्कशॉप के दौरान पीडीसीआरसी के प्रिंसिपल डॉ.गौरव भारद्वाज, विशनगर, गुजरात के प्रोफेसर डॉ. अनिल मनुगुट्टी और जयपुर के प्रोफेसर डॉ.अनुरूप राय ने दो दिनों में 15 से अधिक फुल माउथ इम्प्लांट सर्जरी की। साथ ही, पीएमयू प्रबंधन की ओर से 100 से अधिक डेंटल इम्प्लांट्स मुफ्त में लगाए गए।

कार्यक्रम की आयोजन समिति में पीडीसीआरसी के पीरियोडॉन्टिक्स विभाग की प्रोफेसर डॉ. नेहा मन्नान चड्ढा, ओरल सर्जरी की सीनियर लेक्चरर डॉ.अलफीशा शेख और रेजिडेन्ट डॉ. समृद्धि मेहरा का विशेष योगदान रहा। इस सफल वर्कशॉप के माध्यम से पीडीसीआरसी ने न केवल नवीनतम डेंटल इम्प्लांट सर्जरी विधियों का प्रदर्शन किया, बल्कि विभिन्न देशों के विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करके, देश-विदेश के डेंटल समुदाय को एक मंच पर लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हिन्दू सम्मलेन को लेकर बैठक

बांसवाड़ा, छोटीसरवन भाटिया स्थित वीर एकलव्य उमावि में मण्डल पालकों की बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के चतुर्थ कार्यक्रम के निमित्त विराट हिन्दू सम्मेलन में भजन मण्डली, गंगाजल कलश यात्रा, काव्यपाठ, प्रतिभा सम्मान समारोह, धर्म सभा व ठाम सज्जा के कार्यक्रमों की रचना बनाई गई।

विराट हिन्दू सम्मेलन को लेकर मण्डल पालकों ने मण्डल की क्रियान्वयन टोली, संरक्षण मण्डल, आयोजक टोली व मार्गदर्शक टोली का निर्माण किया। टोली निर्माण के समय सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक टोली, मठ व मन्दिरों के प्रमुख, साधु-संत, मेट व कोतवाल को मुख्य रूप से सहभागिता निभाने का आठाह किया गया। जिला कार्यवाह कन्हैयालाल ने बताया कि इन आयोजनों से सनातन संस्कृति का जागरण होगा व सभी की सहभागिता भी बनेगी। मण्डल स्तर पर होने वाले कार्यक्रम 18 जनवरी से 8 फरवरी 2026 रहेंगे। संचालन बांसवाड़ा परियोजना पूर्णकालिक विद्या सिंह ने किया। बैठक में संजय दानपुर, सतीश सोनी व ईश्वर कलाल छोटी सरवन, दीलिप रूंजिया, रमेश घोडी तेजपुर, मानसिंह मईडा व नारायण मूलिया मौजूद रहे। खण्ड की बैठक आगामी 21 दिसम्बर को वीर एकलव्य उमावि भाटिया में रखी गई है।

ज्ञापन सौंपा

कपासन, (निसं)। कपासन के मुंगाना गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन क्षितठास्त होने के बाद सरकारी आदेश पर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। भवन के अभाव में विद्यार्थी अब महात्मा गांधी राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक मंदिर के आश्रम में अस्थायी जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने में उपखंड अधिकारी (एसडीएम) को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि भवन न होने के कारण विद्यालय दो पारियों में संचालित हो रहा है।

सौंपा ज्ञापन

डूंगरपुर। विद्युत निगम के 25 मार्च 25 के आदेश के अनुसार विद्युत पेंशनर के मेडिकल बिल का भुगतान एक महीने में करने सभी पेंशनर के परिचय पत्र देने पेंशनर के 70-75-80 साल पूरे होने पर निगम रिकॉर्ड के हिसाब से पेंशन वृद्धि करने जीवित प्रमाण पत्र में सरलता के साथ लागू करने के आदेश के बावजूद भी मेडिकल बिल का तय समय में भुगतान नहीं होने अब तक परिचय पत्र नहीं देने पेंशनर के लिए एक रुम की व्यवस्था नहीं करने फिक्सेशन बकाया होने की समस्या को लेकर संगठन जिला मंत्री जयंतीलाल पंड्या जिला संगठन मंत्री मांगीलाल पंचाल ने आज निगम के अधीक्षण अभियंता दोषी को ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की है।

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बामनिया का किया सम्मान

बांसवाड़ा, कांग्रेस के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया का सेवादल कांग्रेस ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में सम्मान किया। सेवादल के पदाधिकारियों ने बामनिया को पुष्प मालाओं से लाद दिया। सेवादल जिला संयोजक धीरजमल डामोर ने कहा कि अर्जुन बामनिया को आला कमान ने जिस भूमिका के लिए चुना है वो पार्टी के लिए अच्छा निर्णय है।

अर्जुन बामनिया ने पार्टी के लिए काफी वर्षो से विभिन्न पद पर रहकर पार्टी की सेवा की है और सेवादल उनको ये विश्वास दिलाता है कि उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी। हमारा संगठन और पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खडे रहेंगे और अपना सर्वोच्च देने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष रमेशचंद्र पंड्या, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार विनोद दादा पाठक, रुक्मणि आर्य आदि ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर जिला प्रवक्ता एडवोकेट इमरान खान पठान ने बताया कि इस दौरान आशीष मेहता, नवाब फौजदार, धर्मेंद्र तेली, शाहरुख खान, सोना ताबियार, रफीक मंसूरी, सईद परवाना, नाथूराम, प्रकाश व्यास, रुक्मणी आर्य, प्रदीप डामोर, कांतिलाल, भुरजी मईडा, मोहन परमार, दलजी पाटीदार, परशुराम राणा गणेश लाल, आनंद मुनिया, राजेश मीणा, मिलन, बहादुर, नाथ, बसंती देवी, बालेश्वर आदि मौजूद रहे।

गुणात्मक परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्यशाला में दिया लक्ष्यबद्ध अध्ययन का मार्गदर्शन

बांसवाड़ा, ठीकरिया स्थित राबाउमावि में ब्लॉक बांसवाडा के बारहवीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र-छात्राओं के लिए गुणात्मक परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्यशाला के दूसरे दिन जिले के शिक्षाधिकारियों ने सहभागिता कर विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयदीप पुरोहित ने कहा कि प्रतिभा का सही मार्गदर्शन समय पर मिले तो परिणाम स्वत: श्रेष्ठ होते हैं। यह कार्यशाला विद्यार्थियों को विषयों की गहराई समझने, आत्मविश्वास विकसित करने एवं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सशक्त मंच प्रदान कर रही है।

- **कठिन विषयों को सरल रणनीति के साथ पढ़ना और शंका समाधान पर विशेष ध्यान देना ही गुणात्मक परिणाम उन्नयन का आधार है**

उन्होंने नियमित अध्ययन, आत्ममूल्यांकन और अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार जैन ने कहा कि चयनित टॉपर विद्यार्थियों पर अब अन्य छात्रों के लिए उदाहरण बनने की जिम्मेदारी भी है। कठिन विषयों को सरल रणनीति के साथ पढना और शंका समाधान पर विशेष ध्यान देना ही गुणात्मक परिणाम उन्नयन का आधार है। उन्होंने विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे मार्गदर्शन की सराहना की। अरथूना की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माया सेमसन ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी परिवेश में मानसिक संतुलन, समय प्रबंधन और निरंतर अभ्यास अत्यंत आवश्यक है।

इस प्रकार की कार्यशालाएं विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण एवं आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। उन्होंने छात्राओं को विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हितेश चन्द्र स्वर्णकार एवं कार्यशाला प्रभारी शोभा जैन मौजूद रहे।

शिक्षाधिकारियों ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर परीक्षा तैयारी संबंधी व्यावहारिक सुझाव भी दिए। ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों से चयनित बारहवीं विज्ञान वर्ग के 32 टॉपर छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान तथा गणित विषय का गहन शिक्षण कराया जा रहा है। कार्यशाला के दौरान प्रधानाचार्य शोभा जैन, हरेंद्र जोशी एवं रीतेश जैन ने सतत पुनरावलोकन कर आगामी कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।

कार्यालय नगर परिषद, राजसमन्द जिला राजसमन्द

क्रमांक :- नपरा/भूमि/2025-26/8018 दिनांक 17.12.25

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न प्रार्थियों द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 की अधिनियम संख्या 18) की धारा 69-क के संशोधित (2021) के अन्तर्गत निम्न स्थान व पडौस के मध्य स्थित अपने भूखण्ड/भवन के पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	स्थान	क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	पड़ौस	
1.	श्री शान्तिलाल सालवी पिता भेरूलाल सालवी	नई आबादी कांकरोली	600.00	पूर्व	भाई देवकीनन्दन के हिस्से का मकान
				पश्चिम	भाई मोहनलाल के हिस्से का मकान
				उत्तर	आम रास्ता
				दक्षिण	आम रास्ता
2.	श्री बाबुलाल परमार पिता भंवरलाल परमार, श्री देवेन्द्र शोभालाल मेहता पिता शोभालाल नवलराम मेहता, विपिन सोलंकी पिता दिनेश कुमार सोलंकी	जे.के. मोड कांकरोली	1000.00	पूर्व	राहुल, हर्षिता, महेन्द्र कुमार, रमेशचन्द्र, ललित कुमार एवं रूकमणी देवी की भूमि
				पश्चिम	प्लॉट सं. 5 शंकरजी तेली
				उत्तर	खेल मैदान
				दक्षिण	आम रास्ता
3.	श्री राहुल साहु, हर्षिता साहु पिता ख्यालीलाल, महेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल	जे.के. मोड कांकरोली	1710.00	पूर्व	रमेश जी तेली का प्लाट
				पश्चिम	बाबुलाल परमार, देवेन्द्र, शोभालाल, विपिन कुमार का प्लॉट
				उत्तर	खेल मैदान, रूकमणी का प्लॉट
				दक्षिण	आम रास्ता
4.	श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी कन्हैयालाल तेली	नया बाजार कांकरोली	858.00	पूर्व	केसुलाल कोठारी का मकान
				पश्चिम	हेमन्त नेणवा का मकान
				उत्तर	रोड़
				दक्षिण	भंवरलाल पन्नालाल कुम्हार का मकान
5.	श्री सलीम हुसैन पिता नाथु बक्ष	माटा मोहल्ला कांकरोली	628.12	पूर्व	गवाड़ी का रास्ता
				पश्चिम	अब्दुल रसीद का मकान
				उत्तर	आम रास्ता
				दक्षिण	अहमद भाई का मकान
6.	श्री भावेश सांचीहर पिता ओमप्रकाश सांचीहर एवं श्री कमल सांचीहर पिता ओमप्रकाश सांचीहर	द्वारिकाधीश मन्दिर मार्ग कांकरोली	1662.00	पूर्व	परमानन्द सनाढ्य का मकान
				पश्चिम	ईश्वरजी सनाढ्य का मकान
				उत्तर	मन्दिर मार्ग
				दक्षिण	हाथी गली
7.	श्री रतनलाल बाकलीवाल पिता नन्दलाल बाकलीवाल	छीपा मोहल्ला कांकरोली	1200.00	पूर्व	कन्हैयालाल छीपा का मकान
				पश्चिम	दीपचन्द कोठारी का मकान
				उत्तर	आम रास्ता
				दक्षिण	आम रास्ता
8.	श्री छोटूलाल जैन पिता वरदीचन्द जैन	नई आबादी कांकरोली	1600.00	पूर्व	प्रकाशजी लढ्ढा का मकान
				पश्चिम	देवीलाल शर्मा का मकान
				उत्तर	आम रास्ता
				दक्षिण	रोशनलाल पिता वरदीचन्द का मकान
9.	श्री रमेशचन्द्र हाडा पिता कन्हैयालाल तेली	जे.के. मोड कांकरोली	1165.00	पूर्व	ललित तेली का मकान
				पश्चिम	राहुल, हर्षिता, महेन्द्र कुमार की भूमि
				उत्तर	रूकमणी देवी की भूमि
				दक्षिण	आम रास्ता
10.	श्री प्रकाशचन्द्र जोशी पिता परमानन्द जोशी	गांधी पार्क के सामने	944.00	पूर्व	सुन्दर टॉकिज सिनेमा रोड़
				पश्चिम	नवलराम पालीवाल का मकान
				उत्तर	गली एवं धर्मशाला
				दक्षिण	स्व. श्री कन्हैयालाल का मकान एवं दुकान
11.	श्री ललित कुमार साहु पिता कन्हैयालाल साहु	जे.के. मोड़ कांकरोली	1105.00	पूर्व	शशी गेस्ट हाउस भवन व होटल
				पश्चिम	रमेशचन्द्र का भूखण्ड
				उत्तर	रूकमणी देवी का भूखण्ड
				दक्षिण	आम रास्ता
12.	श्री संतोष अग्रवाल, हरिश अग्रवाल पिता जगदीशलाल अग्रवाल	सुरभि कॉपलेक्स के सामने नाथद्वारा रोड़ कांकरोली	553.12	पूर्व	सिंचाई विभाग की नहर
				पश्चिम	आम रास्ता
				उत्तर	किशन, शम्भूलाल तेली का मकान
				दक्षिण	सुंदरलाल शर्मा का मकान
13.	श्रीमती उषा देवी पत्नी अनील कुमार जैन	हेड पोस्ट ऑफिस के सामने वाली गली कांकरोली	1250.00	पूर्व	मियाराम भील का मकान
				पश्चिम	आम रास्ता व नहर
				उत्तर	बबली देवी पत्नी राजेश शर्मा का मकान
				दक्षिण	आम रास्ता
14.	श्री भगवतीलाल प्रजापत एवं मनोज प्रजापत पिता स्व. श्री लादुराम उर्फ लादुलाल	बस स्टेण्ड के पास कांकरोली	918.00	पूर्व	बाबुलाल कुम्हार का मकान
				पश्चिम	भंवरजी कुम्हार का मकान
				उत्तर	नारायणजी तेली का मकान
				दक्षिण	आम रास्ता
15.	श्रीमती हसीन बानु पत्नी दीना मोहम्मद	चान्दपोल अन्दर मस्जिद वाली गली	855.875	पूर्व	गली व तैयब बोहरा का मकान
				पश्चिम	गली
				उत्तर	बाबुलाल डायर का मकान
				दक्षिण	सामलाती गली
16.	श्रीमती सायरा बानु पत्नी रईस मोहम्मद	नायकवाड़ी राजनगर	362.50	पूर्व	भंवरलाल लड्ढा का खेत वर्तमान में बसन्तीलाल लड्ढा का मकान
				पश्चिम	आम रास्ता
				उत्तर	अलाबक्ष एवं चान्दुजी पिनारा का मकान
				दक्षिण	नवलाजी रामाजी का मकान एवं वर्तमान में प्रकाशजी बड़ौला का मकान
17.	श्री मोहनलाल सालवी पिता श्री श्री भेरूलाल सालवी	नई आबादी कांकरोली	600.00	पूर्व	भाई शान्तिलाल के हिस्से का मकान
				पश्चिम	कैलाश जी नेहरिया का मकान
				उत्तर	आम रास्ता
				दक्षिण	आम रास्ता
18.	श्री देवकीनन्दन सालवी पिता भेरूलाल सालवी	नई आबादी कांकरोली	600.00	पूर्व	मदन सियाल का मकान
				पश्चिम	भाई शान्तिलाल के हिस्से का मकान
				उत्तर	आम रास्ता
				दक्षिण	आम रास्ता
19.	श्रीमती सीमा साहु पत्नी मनोज साहु	छीपा मोहल्ला कांकरोली	882.00	पूर्व	जयंत कुमार पालीवाल पिता अम्बालाल पालीवाल की दुकाने
				पश्चिम	गोपाल छीपा का मकान
				उत्तर	आम रास्ता
				दक्षिण	भगवतीलाल पालीवाल का मकान
20.	श्री दिनेश कुमार पिता भंवरलाल तेली	जलचक्की रोड कांकरोली मुख्य सड़क	770.25	पूर्व	आम रास्ता
				पश्चिम	जलचक्की से नाथद्वारा रोड
				उत्तर	अनन्तनारायण जी का मकान
				दक्षिण	दीपक साहु का मकान
21.	श्री कैलाशचन्द्र पुरोहित पिता मोहनलाल पुरोहित	राधुन गली कांकरोली	1416.00	पूर्व	गोवधनलाल छीपा का मकान
				पश्चिम	रामसुख नूवाल का मकान
				उत्तर	रास्ता
				दक्षिण	भगवतीलाल जेली का मकान
22.	श्री फिरोज खान पिता ताहिर खान	चान्दपोल बाहर कांकरोली	724.5	पूर्व	इब्राहिम बोहरा का मकान
				पश्चिम	सतीमाता का चबुतरा
				उत्तर	आम रास्ता
				दक्षिण	बच्चुजी चमार का मकान

उक्त आवेदन पत्रों के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में आग से चार लोग जिंदा जले, तीन की मौत

तीनों शव सीट पर चिपके हुए मिले, एक गंभीर झुलसे व्यक्ति को जयपुर रेफर किया

- बताया जा रहा है कि पिकअप को ड्राइवर साइड की तरफ किसी वाहन से टक्कर लगी है, टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई
- पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, इसके बाद ही पता लगेगा कि गाड़ी को किसने टक्कर मारी थी

अलवर, (निसं)। अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार देर रात एक पिकअप में आग लग गई। हादसे में तीन लोगों की बुरी तरह जलने से मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर झुलसे व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार हादसा जिले के रैणी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात करीब एक बजे हुआ। एएसआई मोहम्मद आमीन ने बताया कि अंदाजा है कि पिकअप को ड्राइवर साइड की तरफ किसी वाहन से टक्कर लगी है। टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई। तीनों शव सीट पर चिपके हुए मिले। एएसआई ने बताया पिकअप में मिले तीन लोगों के शवों की पहचान मोहित निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। हादसे में घायल ड्राइवर की पहचान हन्नी निवासी झज्जर (हरियाणा) के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है।

अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर आग लगने पिकअप गाड़ी पूरी तरह से जल गई।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में आग देखने के बाद कई गाड़ियां मौके पर ही रुक गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब तक रेस्क्यू शुरू किया गया, तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल गई थी।

पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके बाद ही साफ होगा कि गाड़ी को किसने टक्कर मारी थी। शवों को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पिकअप वाहन के नंबरों से जानकारी मिलने पर वाहन झज्जर (हरियाणा) का पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी है।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार : टोंक जिले की स्पेशल टीम प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अवैध हथियारों के विरुद्ध के तहत उनकी टीम ने निवाई सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात्रि को क्षैत्र स्थित मुंडिया कट के पास से आरोपी मोहिद खान पुत्र रुस्तम खान निवासी खिड़की थाना बरौनी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की गई।

डीएसटी टीम ने आरोपी को निवाई सदर थाना पुलिस को सौंप दिया, जिसके खिलाफ थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निवाई सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है।

दस्तावेज सत्यापन की तिथि बढ़ाई

अजमेर, (कासं)। पटवार परीक्षा 2025 के तहत सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि आगामी 22 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है। उप निबन्धक (भू अभिलेख) रवीन्द्र कुमार ने बताया कि अधिकाधिक अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व में तीन दिन का अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए 17 दिसम्बर तक दस्तावेज सत्यापन कार्य हुआ जिसमें साढ़े छह हजार से अधिक अभ्यर्थियों को सत्यापन का लाभ मिला। शेष अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आगामी 22 दिसम्बर की शाम पांच बजे तक दस्तावेज सत्यापन कराने को कहा गया है। यह कार्य यथावत आरआरटीआई जयपुर रोड अजमेर में सम्पादित होगा।

परीणाम जारी

अजमेर, (कासं)। 11वीं बटालियन आरएसी वजीराबाद रियर मुख्यालय नारेली के लिए कॉन्स्टेबल सामान्य की भर्ती शारीरिक दक्षता एवं माप तौल परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। इसे राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। 11वीं बटालियन के कमाण्डेन्ट केवल राम ने बताया कि बटालियन के रियर मुख्यालय नारेली के नोटिस बोर्ड पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

जोधपुर की कायलाना झील में युवक-युवती के शव मिले

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के कायलाना झील में बुधवार सुबह युवक-युवती के शव मिले। झील किनारे एक एक्टिवा, बैग,मोबाइल और जैकेट भी मिला। सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। मामला आत्महत्या या किसी अन्य कारण से डूबने का है, इसकी जांच की जा रही है। युवक-युवती दोनों पड़ोसी थे। हादसा राजीव गांधी नगर थाने का है।

एएसआई रावल राम ने बताया कि हर्ष परिहार (21) पुत्र राजेश परिहार और चेष्टा धोला (20) पुत्री विकास धोला मंगलवार को खांडा फलसा थाना क्षेत्र स्थित अपने घरों से निकले थे। दोनों एक ही जाति के थे और पड़ोसी थे। परिवार ने मंगलवार को सिटी पुलिस थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। गोताखोरों की टीम ने दोनों को बॉडी को बाहर निकाला।

- मामला आत्महत्या या किसी अन्य कारण से डूबने का है, इसकी जांच की जा रही है

एएसआई ने बताया कि मंगलवार शाम को करीब पांच बजे कायलाना झील के आगे तखत सागर के पास दोनों की स्कूटी और बैग मिले थे। इसके बाद कायलाना पुलिस चौकी के सिपाही दिनेश सोडा और गोताखोर भरत चौधरी के साथ मौके पर जाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने के कारण दोनों के शव नहीं मिल सके। इसके बाद आज सुबह फिर से अभियान शुरू किया। शव गहरे पानी में फंसे हुए मिले। इस दौरान मौके पर परिजन भी मौजूद थे। शवों को एमडीएम अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है।

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर पालिका, सादड़ी (जिला-पाली) राज.
(आपकी सेवा में सदैव तत्पर)
पताः मैन बस स्टेण्ड, सादड़ी
Ph.-02934-285022 email: npsadri1979@yahoo.com, gmail.com
क्रमांक : न.पा.सा./2025/4232–4234 दिनांक 15.12.2025
-:: Notice Inviting Bid ::-
Bid for subject matters of procurement are invited from intreseted bidders upto (date)& (time). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal. (https://sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in) of the state departmental website.
UBN NO:- DLB2526WSOB27334
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादड़ी
राज.संवाद/सी/25/15940

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान
E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419
क्रमांक :–न.प.सु/विकास शाखा/2025/9280 दिनांक :– 11.12.2025
:–ई–निविदा सूचना–2025–26:–
नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निविदा दिनांक 22.12.2025 तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक (DLB2526WSOB26910), (DLB2526WSOB26911), (DLB2526WSOB26913), (DLB2526WSOB26914) है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।
आयुक्त
नगर परिषद सुजानगढ
राज.संवाद/सी/25/15979

चोरी करने वाले तीन बदमाश सात घंटे में गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। अलवर के अखेपुरा थाना पुलिस ने दुकान में चोरी कर नकदी पार करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के एएसआई घनश्याम शर्मा ने बताया कि परिवादी महेंद्र जैन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अशोका टॉकीज से पुलिस लाइन की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित उनकी नवकार ट्रेडर्स के नाम से दुकान व गोदाम में चोरों ने वारदात की थी।

- छत का ताला तोड़कर दुकान में घुसे और गल्ला तोड़कर 65 हजार रुपये ले गए थे

पुलिस ने दुकान में चोरी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

परिवादी के अनुसार सोमवार रात चोर दुकान के पीछे छत पर चढ़े और सीढ़ियों का ताला तोड़कर नीचे उतरे। इसके बाद दराज से 65 हजार रुपये नकद और एक आधार कार्ड चोरी कर ले गए। परिवादी ने मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे थाने में शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सूचना के आधार पर कांस्टेबल विक्रम और कांस्टेबल गिर्राज की टीम ने तीन आरोपियों-लोकेश कुमार निवासी नवाबपुरा मोहल्ला, राहुल बैरवा निवासी गाय वाला मोहल्ला और राहुल कोली निवासी ज्योति नगर, 200 फुट रोड को मंगलवार शाम छह बजे ही डिटेन कर थाने ले आए। बुधवार को सात घंटे में वारदात का खुलासा कर दिया है। वारदात में चोरी गई नकदी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।

सड़क नहीं बनने पर कलैक्टर व एसडीएम की संपत्ति कुर्क होगी

कोर्ट ने चेतावनी दी कि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और गिरफ्तार भी किया जा सकता है

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में सड़क निर्माण के आदेश की अनदेखी प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। भोपालगढ़ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका ईओ को चेतावनी दी है कि यदि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सिविल न्यायाधीश ने स्थायी लोक अदालत के पंचाट (लोक अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया फैसला) की पालना नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहन जाखड़ ने बताया कि भोपालगढ़ निवासी रामकिशोर और अन्य ने एक सार्वजनिक रास्ते को लेकर स्थायी लोक अदालत में परिवाद पेश किया था। लोक अदालत ने सुनवाई के बाद 27 सितंबर 2023 को वहां सड़क निर्माण का आदेश दिया था। अधिवक्ता जाखड़ ने बताया कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने उस आदेश की पालना नहीं की। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला के समक्ष अवमानना याचिका पेश की और स्थायी लोक अदालत की डिक्री (फैसले) की पालना करवाने की मांग की।

जिला न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल न्यायाधीश भोपालगढ़ को डिक्री की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में अब सिविल न्यायाधीश ने चारों जिम्मेदार अधिकारियों ईओ नगर पालिका भोपालगढ़, तहसीलदार भोपालगढ़, एसडीएम भोपालगढ़ और जिला कलैक्टर जोधपुर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आगामी 24 दिसंबर तक आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अप्रार्थीगणों (अधिकारियों) की संपत्ति कुर्क करने और गिरफ्तारी वारंट जारी कर डिक्री की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दुरभाष स.0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट. www-udaipurmc.org
क्रमांक : निविजा/2025–26/ई –32 दिनांक :– 16.12.2025
(ई–भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या – ई 32/2025–26
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यो हेतु कुल राशि रु0 58.12 लाख के कुल 03 कार्यो हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यो की प्रारम्भ तिथि 16.12.2025 एवं अंतिम तिथि 29.12.2025 तथा निविदा खुलने की तिथी 30.12.2025 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।
UBN No. UNP2526WSOB00124
अधीक्षण अभियन्ता
नगर निगम, उदयपुर
राज.संवाद/सी/25/15961

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.
गांधी उद्यान–ब्यावर रोड, बिजयनगर
टैलीफोन नम्बर – 01462–230051 ई–मेल :– npvijaynagar@gmail.com
ऑन लाईन निविदा सूचना संख्या 24/2025–26
नगर पालिका बिजयनगर द्वारा राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से सिविल कार्य हेतु ऑन लाईन निविदा निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रीया से वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। ऑन लाईन निविदा सूचना संख्या 24/2025–2026 के कार्य संख्या 01 से 02 की अनुमानित लागत 47.05 लाख है। ऑन लाईन निविदाए दिनांक 15–12–2025 से 26–12–2025 समय सांय 6:00 बजे तक डाउनलोड की जाकर दिनांक 29–12–2025 को निविदा शुल्क, अमानत राशि एंव प्रोसेसिंग शुल्क की UTR Receipt भौतिक रूप से समय 12:00 PM तक कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। ऑन लाईन निविदा की ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक 30–12–2025 समय प्रातः 10:00 बजे खोली जायेगी। अधिक जानकारी वेबसाईट https://sppp.raj.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।
UNB Reference No:- DLB2526A9096
राज.संवाद/सी/25/15916
अधिशाषी अधिकारी

अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा, दो शातिर गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। डीएसटी जोधपुर ग्रामीण और बिलाड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य सप्लायर समेत दो शातिर तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से पांच पिस्टल, पांच मैगजीन, पांच कारतूस और 1.48 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। मुख्य आरोपियों की पहचान ललित सीरवी और दिलजीत पूनिया के रूप में हुई है। ये दोनों जयपुर-जोधपुर हाईवे पर बिलाड़ा बाईपास के पास हथियारों की डील करने पहुंचे थे।

- पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच पिस्टल, पांच मैगजीन, पांच कारतूस और 1.48 लाख रुपए नकद बरामद किए
- दोनों आरोपी जयपुर-जोधपुर हाईवे पर बिलाड़ा बाईपास के पास हथियारों की डील करने पहुंचे थे
- पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपियों ने हथियार कहां से मंगाए थे और किन-किन को सप्लाई किए जाने थे

एएसपी भोपालसिंह लखावत ने बताया कि एसपी नारायण टोगस के निर्देशानुसार पुलिस अवैध हथियारों को लेकर अभियान चला रही है। इसी क्रम में टीम को अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सूचना मिली थी। इस पर टीम ने सी अन्नराज सिंह के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी श्रवण कुमार और थानाधिकारी बिलाड़ा सवाई सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टीम ने बिलाड़ा बाईपास के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मध्यप्रदेश से अवैध हथियार खरीदकर लाए थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी इन हथियारों को कहां काम लेने वाले थे। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ अवैध हथियार तस्करी को लेकर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ललित सीरवी निवासी खारिया मीठापुर, दिलजीत जाट निवासी पिचियाक को गिरफ्तार किया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपियों ने हथियार कहां से मंगाए गए थे और किन-किन को सप्लाई किए जाने थे।

बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतारा

मांगरोल, (निसं)। मांगरोल थाना क्षेत्र के गांव रिंझियां में बेटे ने अपने पिता को धारदार कुठे (एक हथियार) से मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों की सूचना पर मांगरोल थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक की लाश को अपने कब्जे में लेकर उप जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां शव को मोर्चरी में रखा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड बैठाकर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर सोभाग मल मीणा, डॉक्टर आर बी मीणा व अन्य डॉक्टर के साथ मिलकर शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। अंता डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह आढा ने बताया गया कि गृह क्लेस के चलते आए दिन झगड़ा के कारण बेटे ने पिता पर कुठे से हमला कर सिर, पेट व एक हाथ का पंजा काट दिया, जिससे घटना स्थल पर नरोत्तम उर्फ पप्पू पुत्र सूरजमल निवासी रिंझियां की मौत हो गई। मृतक ने पहले वाली पत्नी को छोड़कर सहरिया जाति की औरत से शादी कर रखी थी, सहरिया औरत के साथ गांव ब्रह्मपुर रामगढ के पास थाना किशनगंज क्षेत्र में रहते थे। कभी-कभी अपने गांव रिंझियां आया करता था। मृतक नरोत्तम की पत्नी सरोज सहरिया ने हत्या करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मुलजिम विजय नागर के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया।

राजस्थान युवा बोर्ड
(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार)
सवाई मानसिंह स्टेडियम, प्रथम तल, जयपुर टेलीफैक्स 0141-2741489
क्रमांक :- F.01(15)RYB/2025-26/00021-7863630 जयपुर, दिनांक :- 15/12/2025
शुद्धि पत्र संख्या - 1
''राजस्थान युवा महोत्सव'' का भव्य एवं सफल आयोजन हेतु इवेन्ट मैनेजमेंट (EVENT MANAGEMENT) के सम्पूर्ण कार्य हेतु दक्ष, प्रतिष्ठित व अनुभवी फर्मो/संस्था/कंम्पनी से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ई–निविदा सूचना संख्या 05/2025–26, दिनांक 15.12.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की गई है, जिसमें आंशिक संशोधन कर दिनांक 18.12.2025 दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जा रही है। संशोधन का पूर्ण विवरण राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर की वेबसाईट www.youthboard.rajasthan.gov.in एवं लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in व ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
राज.संवाद/सी/25/15928
सदस्य सचिव

किसान महापंचायत में एथेनॉल फैक्टरी हटने तक आन्दोलन जारी रखने का ऐलान

हनुमानगढ़, (निसं)। जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्टरी के विरोध में आयोजित महापंचायत में किसानों ने भाजपा सरकार पर आम आदमी की जमीन, हवा और पानी छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने फैक्टरी हटने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों से ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि समय आने पर यही काम आएंगे। महापंचायत में राजस्थान के साथ पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। हालांकि प्रशासन से दो घंटे चली बातचीत के बाद आज की महापंचायत को संपन्न कर दिया। अब सात जनवरी को संगरिया में महापंचायत होगी।

- जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्टरी के विरोध में आयोजित महापंचायत में किसानों ने भाजपा सरकार पर हमला बोला
- ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखो, अब सात जनवरी को संगरिया में जुटेंगे : किसान नेता राकेश टिकैत
- टिब्बी की एथेनॉल फैक्टरी से संभावित भूजल एवं प्रदूषण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि टिब्बी में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फैक्टरी के मामले में कहा जा रहा है कि इससे विकास होगा, नौकरी मिलेगी। कहते हैं कि आप विकास का विरोध कर रहे हैं। उन्हें यही कहना है कि जहां फैक्टरी लगेगी वहां जमीन, हवा और पानी दूषित होगा। फैक्टरी शुरू हो गई तो प्रशासन को दूषित पानी दिखाते रहना। ये 14 फैक्टरी के बराबर है, इसलिए टिब्बी की संघर्ष कमेटी जो फैसला लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसा मामला हुआ। मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारा की जमीन हाईवे के रास्ते में आ रही थी। वहां झंडा लगा दिया। सरकार को सड़क का रास्ता बदलना पड़ा। यहां भी झंडा गाड़ दो कि एक किलोमीटर के घेरे में जो ट्रक आएगा वो वापिस नहीं जाएगा। ट्रक नहीं आएगा तो फैक्टरी का सामान कहां जाएगा। टिकैत ने कहा कि प्रशासन 144 लगाता है तो किसान भी उससे दोगुनी धारा लगाएगा। अब फैसला संघर्ष समिति को लेना है। संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष कमेटी के साथ है। अभी तो बीज कानून के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार जमीन छीनना चाहती है। परिवारों को सरकार बांट रही है। इसके खिलाफ लड़ना है। यहां के कलैक्टर ने ट्रैक्टर को हथियार बताया, उनका धन्यवाद। मैं तो कहता हूं कि ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखो। आंदोलन में यही काम आएगा। प्रशासन भले ही रोके लेकिन जहां जाओ ट्रैक्टर लेकर जाओ। आंदोलन में तो ट्रैक्टर जरूर लेकर जाना।

वहीं किसानों ने एथेनॉल फैक्टरी हटाने और 10 व 11 दिसंबर को दर्ज हुए मुकदमे रद्द करने की मांग की। इसी बीच, बुधवार सुबह सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक आदेश सार्वजनिक किया गया। इस आदेश के अनुसार, टिब्बी की एथेनॉल फैक्टरी से संभावित भूजल एवं प्रदूषण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में बीकानेर संभागीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशिष्ट शासन सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। हनुमानगढ़ जिला कलैक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता इसके सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। यह समिति अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।

किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। धान मंडी के मुख्य गेट को छोड़कर अन्य सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और उनके आगे ट्रॉलियां लगाई गई। टिब्बी की घटना से सबक लेते हुए प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। कलैक्ट्रेट से करीब आधा किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया है। कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं, जिससे पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।

चढूनी ने कहा कि किसान मुकदमों से डरने वाला नहीं है। यहां की कमेटी जो निर्णय लेगी वहीं लागू होगा। पूरे देश का किसान यहां के लोगों के साथ खड़ा होगा। सरकार को साफ बताना चाहते हैं कि फैक्टरी बंद करनी है तो मतलब बंद कर दो। किसान की बात हल्के में मत लेना। मुकदमे रद्द कर दो, अगर मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन हरियाणा में भी होगा। उगराहा ने कहा कि आंदोलन तभी खत्म होगा, जब एथेनॉल फैक्टरी हटेगी। पहले सरकार आम आदमी की शिक्षा, रोजगार छीन रही थी। अब बात जमीन, पानी और हवा तक आ गई। एथेनॉल जैसी फैक्ट्रियों से यह सब दूषित हो गया तो आम आदमी कहां जाएगा।

पांच हजार की रिश्वत लेते महिला पटवारी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की श्रीगंगानगर टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए लोंगवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ की महिला पटवारी ममता को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत परिवादी उसकी माता के नाम चक 3 एलजीडब्ल्यू तथा चक 1 पीबीएन की भूमि के इंतकाल दर्ज करने की एवज मांगी गई थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी की श्रीगंगानगर टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी माता जी के नाम चक 3 एलजीडब्ल्यू तथा चक 1 पीबीएन की जरिये वैयनामा क्रय की गई भूमि का इंतकाल दर्ज करने की एवज में महिला पटवारी ममता ने 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा 5 हजार रुपये रिश्वत के पूर्व में ले लिये। अब शेष 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही है। जिस पर एसीबी श्रीगंगानगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन कुमार मीणा ने ट्रेप की कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी ममता को पांच हजार रुपये बतौर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान
No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/217 - 219 Date :- 12/12/2025
ई-निविदा सूचना संख्या 63/2025-26
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदा कार्यो की कुल लागत	: रूपये 248.87 लाख (09 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	: 16.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 01.01.2026 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	: 16.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 01.01.2026 को सांयः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	: 02.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. : ITU2526WSOB00357 To ITU2526WSOB00365
अधिशाषी अभियन्ता - प्रथम
उदयपुर विकास प्राधिकरण
राज.संवाद/सी/25/15921

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL RAJSAMAND
Zila Parishad Road, Rajnagar, Rajsamand Pin 313324
Email :- rajsamandnagarpalika@gmail.com Telephone No. 02952-220034
S. No. F ( )/MCR/Processing Plant/RFP/2025/7702 Date :- 11.12.2025
Corrigendum-I
Technical and financial bids in signle stage two envelops un conditional sealed bid has been invited by Municipal Council Rajsamand to vide SN. 6422 Dated 07-11-2025 submission dated 12-12-2025 at 06:00 PM UBN No. DLB2526WLOB23741 for Design, construction, establishment and development of processing plant and required development work and maintenance of Engineered sanitary landfill site and o&m the 20 years having a minimum adequate capacity for Rajsamand and scalable further as per requirement on VGF basis. The date & time are hereby revised as details below.
Schedule of Bidding Process

Important Events	पूर्वानुसार तिथि व समय	संशोधित तिथि व समय
Estimated Cost	680.00	680.00
Publishing Date & Time	11.11.2025 at 06:00 PM	11.11.2025 at 06:00 PM
Bid Download start Date & Time	12.11.2025 at 09:00 AM	12.11.2025 at 09:00 AM
Bid submission End Date & Time	11.12.2025 at 06:00 PM on http://eproc.rajasthan.gov.in	23-12-2025 at 06:00 PM on http://eproc.rajasthan.gov.in
Physically Document Submission Date & Time	12.12.2025 at 01:00 PM	24-12-2025 at 01:00 PM
Technical Bid Opening Date & Time	12.12.2025 at 04:00 PM at ULB Rajsamand	24-12-2025 at 04:00 PM at ULB Rajsamand

Details may be seen at the state public procurement portal http//www.sppp.rajasthan.gov.in, http//www.eproc.rajasthan.gov.in in and may be downloaded from these website.
Commissioner
Municipal Council Rajsamand
Raj.Samwad/C/25/15986

आरजीएचएस योजना में वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक 2267 करोड़ रुपये के दावे स्वीकृत

चिकित्सा विभाग ने बीकानेर में निजी डायग्नोस्टिक लैब को योजना से किया डी-पैनल

- राज्य सरकार ने 6 कॉनफेड मेडीकल स्टोर्स एवं 1 निजी अस्पताल को किया निलंबित
- अनियमितताओं की जांच व ऑडिट के लिए कंट्रोल एवं परफॉरमेंस ऑडिट प्रकोष्ठ एवं एंटी फ्रॉड यूनिट
- अस्पतालों को 1260 करोड़ और फार्मेसीज को 932 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में अनियमितताओं के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से सभी सेवारत व सेवानिवृत कर्मचारी एवं अधिकारी, मंत्रीगण, विधायक, पूर्व विधायक को व्यापक कैशलेस चिकित्सा कवरेज उपलब्ध करवाकर आईपीडी, डेकेयर, ओपीडी, जांच एवं दवाइयों की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना से लाभार्थियों को प्रदेश में व्यापक कैशलेस चिकित्सा कवरेज सुविधा मिल रही है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में वित्त वर्ष 2021-22 में 687.38 करोड़ रुपये, 2022-23 में 3057.38, 2023-24 में 3519.40 और वित्त वर्ष 2024-25 में 4290 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई। इस योजना में प्रतिदिन औसत 45 हजार से अधिक दावे प्राप्त हुए हैं। योजना अंतर्गत बेहतर समन्वय व मॉनिटरिंग की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला स्तर पर उत्तरदायी बनाया गया है। इससे योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है।

आरजीएचएस के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आईपीडी में 1311.25 करोड़ रुपये, डे-केयर में 411.78 करोड़ रुपये, ओपीडी परामर्श व जांच पर 649.99 करोड़ रुपये एवं दवाईयों पर 1889.85 करोड़ रुपये के दावे तथा वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक कुल 2267 करोड़ रुपये के दावे स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2025-26 में अस्पतालों को 1260 करोड़ रुपये एवं फार्मेसीज को 932 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरजीएचएस में अनियमितता करने पर मंगलवार को बीकानेर में निजी डायग्नोस्टिक लैब को योजना से डी-पैनल कर 6 कॉनफेड मेडीकल स्टोर्स एवं 1 निजी अस्पताल को भी योजना से निलंबित किया गया है। अनियमितता व धोखाधड़ी करने पर विभाग ने वर्ष 2025 में 10 मामलों में संबंधित फार्मेसी, चिकित्सक व लाभार्थियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

आरजीएचएस सुविधा को बेहतर व पारदर्शी बनाने के लिए अप्रैल 2025 से अब तक 159 अनुमोदित निजी चिकित्सालयों को योजना से निलंबित कर टीएमएस आईडी ब्लॉक की गई है तथा 5 अस्पतालों को योजना से डी-पैनल किया गया है। आवश्यक सुनवाई कर अस्पतालों के विरूद्ध 26.12 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई गई, जिसमें से 25.07 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। वर्तमान में 65 निजी चिकित्सालय योजना से निलंबित हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनियमितता एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों में अप्रैल 2025 से अब तक 137 फार्मेसी को निलंबित कर उनकी टीएमएस आईडी ब्लॉक की गई है। इसके अतिरिक्त योजना अन्तर्गत कैशलेस दवा वितरण से इन्कार करने के कारण 411 फार्मेसी स्टोर एवं ड्रग लाइसेंस लैप्स हो जाने के कारण 944 फार्मेसी स्टोर को निलंबित किया गया है। साथ ही, मेडीकल स्टोर्स के विरुद्ध 39.79 लाख रुपये की पैनल्टी लगाई गई है, जिसमें से 35.42 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसी प्रकार अप्रैल 2025 से अब तक कुल 4 लैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर को भी योजना से निलंबित किया गया है। अनियमितताओं में संलिप्त आरजीएचएस कार्डधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1032 लाभार्थियों के कार्ड ब्लॉक किये गये हैं। गंभीर अनियमितता व धोखाधड़ी के 61 मामलों में कार्मिक को सेवा से निलंबित करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को लिखा जा चुका है। इनमें से 23 कार्मिकों एवं 7 चिकित्सकों को निलंबित किया गया है। इसी प्रकार 11 चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 493 लाभार्थियों के विरूद्ध कार्ड के दुरूपयोग के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को प्रकरण भेजे गये हैं। इनमें से पुलिस विभाग के 137, स्कूल शिक्षा विभाग के 258, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 60, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 23 एवं आयुर्वेद विभाग के 15 कार्मिक सम्मिलित हैं। दावों के भुगतान के लिए एफआईएफओ प्रक्रिया आरजीएचएस योजना में विभिन्न अनुमोदित निजी चिकित्सालयों, फार्मेसी, जांच केन्द्र व कार्डधारकों के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच व ऑडिट के लिए क्वालिटी कन्ट्रोल एवं परफॉरमेंस ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त एंटी फ्रॉड यूनिट का भी गठन किया गया है। योजना में क्लेम यूनिट व क्लेम रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है, जिसके जरिए निरंतर जांच व सुनवाई की जा रही है।

जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किए पांच आरोपी

- आरोपियों में गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल व उनके बेटे हेमंत मित्तल, श्याम ट्यूबवेल के मैनेजर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन शामिल हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने जल जीवन मिशन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमंत मित्तल (उर्फ गोलू), श्याम ट्यूबवेल के मैनेजर एवं लायजनिंग अधिकारी उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन शामिल हैं। जिन्हें जयपुर शहर के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

एसीबी पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि यह मुकदमा 2023 में दर्ज किया गया था। इसमें श्याम ट्यूबवेल कंपनी, उसके मालिक पदमचंद जैन, गणपति ट्यूबवेल कंपनी और उसके मालिक महेश कुमार मित्तल पर पीएचईडी के बहरोड़ अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी, नीमराना सहायक अभियंता राकेश चौहान तथा कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार से सांठगांठ कर जल जीवन मिशन के टैंडर हासिल करने के आरोप लगे थे।

इन आरोपियों पर काम में गंभीर अनियमितताएं बरतने, घटिया सामग्री का उपयोग करने और मनमाने ढंग से मेजरमेंट बुक (एमबी) भरकर करोड़ों रुपये की अवैध प्राप्ति करने का भी आरोप है। एसीबी के पास आरोपियों की आपसी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, जो मिलीभगत के सबूत है।

इस मामले की त्वरित जांच के लिए एसपी महावीर सिंह राणावत की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी। जिसमें एएसपी हिमांशु कुलदीप, भूपेंद्र और महावीर प्रसाद शर्मा शामिल हैं। एसआईटी ने तकनीकी सबूतों और ट्रांसक्रिप्ट का गहन विश्लेषण किया। पहले छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है। शेष फरार आरोपियों में से इन पांच को जयपुर के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

गोविंद गुप्ता ने बताया कि 2023 में आरोपियों को पीएचईडी अधिकारियों से 2.20 लाख रुपये की रिश्वत लेते-देते पकड़ा था। डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह और एसपी महावीर सिंह राणावत के निर्देशन में एएसपी भूपेंद्र की टीम ने यह कार्रवाई की। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में पूछताछ और आगे की जांच जारी है।

टीकाराम जूली ने न बजट पढ़ा और ना ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति समझी : चतुर्वेदी

- राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर किया पलटवार

जयपुर। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टीकाराम जूली ने न तो राज्य सरकार का बजट ठीक से पढ़ा है और न ही राजस्थान की वास्तविक आर्थिक स्थिति को समझा है। कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है और तथ्यों से दूर बयानबाजी कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वर्ष 2013 में जब भाजपा सरकार बनी थी, तब राजस्थान की आर्थिक स्थिति घाटे में थी, लेकिन भाजपा सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी। इसके बाद कांग्रेस शासनकाल में एक बार फिर राज्य की अर्थव्यवस्था घाटे में चली गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और राज्य के संसाधनों में लगातार वृद्धि हो रही हैं।

ईआरसीपी परियोजना और यमुना जल समझौते को लेकर अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्षों तक इन मुद्दों पर केवल राजनीति करती रही, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने आर्थिक प्रबंधन के आधार पर ईआरसीपी पर काम शुरू किया है। इसी तरह यमुना जल को लेकर 50 वर्षों तक केवल राजनीति हुई, लेकिन मौजूदा सरकार के आने के बाद इस दिशा में ठोस पहल हुई है और डीपीआर तैयार की जा रही है।

अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में लगातार ठोस और परिणामोन्मुख कार्य कर रही है। पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े आयोजन कर सरकार ने विकास और निवेश को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी।

उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस ईमानदार है तो विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाकर बहस कराई जाए। इसमें पिछली कांग्रेस सरकार के पांच साल और वर्तमान सरकार के दो साल के कार्यों की तुलना हो, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।

मनरेगा के नाम बदलने के मुद्दे पर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा से जुड़ी नीतियों में कई सुधार किए हैं। उनके लिए नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। मौजूदा सरकार मनरेगा में समय पर भुगतान, स्थायी विकास से जुड़े कार्यों और अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार देने पर फोकस कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस अफवाह, भ्रम और नकारात्मकता के सहारे राजनीति कर रही है।

सांस्कृतिक संध्या में लोक-संगीत और प्रदेश की समृद्ध संस्कृति नजर आई

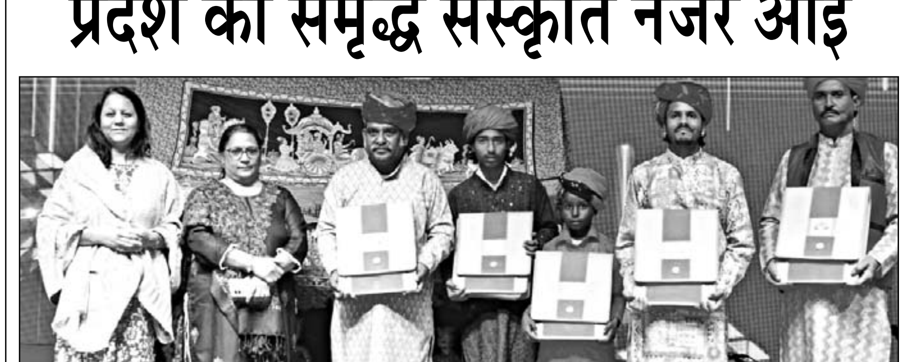

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संयुक्त निदेशक क्षिप्रा भटनागर ने मकरंद देशपांडे को डीआईपीआर की ओर से किट गिफ्ट किया।

- भपंग वादन, चंग की थाप, बांसुरी की सुरीली धुन और कठपुतली शो रहे आकर्षण का केंद्र
- बॉलीवुड एक्टर, राइटर मकरंद देशपांडे ने कठपुतली कलाकारी के अद्भुत हुनर की जोरदार प्रशंसा

जयपुर । सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से राज्य सरकार के कार्यकाल के शानदार दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जवाहर कला केन्द्र में 15 दिसम्बर से आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में तीसरे दिन बुधवार को सांस्कृतिक संध्या में भपंग वादन, चंग की थाप, बांसुरी की सुरीली धुनों और काठ की पुतलियों की जीवंत अदाओं ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया।

पर्यटन विभाग के सहयोग से सुसज्जित सांस्कृतिक संध्या में यूसुफ खाँ एवं उनके समूह ने भपंग वादन के माध्यम से कैसो आ गयो जमानो रे और दुनिया में भाया देख ले जैसे लोकगीतों की प्रस्तुति देकर खूब तालियाँ बटोरीं। वहीं चूरू के श्याम मित्र मण्डल ने चंग की जोशीली थाप और बांसुरी की मधुर तान के साथ लोकधुनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण कठपुतली लोक कलाकार राजू भाट रहे, जिन्होंने ढोलक की थाप पर उंगलियों पर काठ की पुतलियों को नचाते हुए महाराजा अमरसिंह की कहानी प्रस्तुत कर दर्शकों को जीवंत अनुभूति कराई। प्रदर्शनी देखने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर, राइटर और डायरेक्टर मकरंद देशपांडे ने कठपुतली कलाकारी के अद्भुत हुनर की जोरदार प्रशंसा करते हुए कहा कि लोक कलाओं को संजोकर रखा जाए, यह कलाएं हमारी धरोहर हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से यह निःशुल्क कला प्रदर्शन है किन्तु कठपुतली कला अद्भुत और अलौकिक है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संयुक्त निदेशक क्षिप्रा भटनागर ने मकरंद देशपांडे को डीआईपीआर की ओर से किट गिफ्ट किया, उनका स्वागत किया, वहीं कलाकारों को भी मंच पर सम्मानित किया। इससे पूर्व राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी क्षिप्रा शर्मा किस्सागोई कला के अंतर्गत मोर और मोरनी की लोककथा सुनाकर श्रोताओं को कथाओं की दुनिया में ले गईं। इस अवसर पर विभाग की सहायक निदेशक कविता जोशी ने प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

पिछले साल की तुलना में 14200 करोड़ रुपये अधिक राजस्व मिला

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस से बदली तस्वीर, प्रदेश के राजस्व में हुई वृद्धि

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्व सुधार और वृद्धि के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। डिजिटलाइजेशन और तकनीक के प्रयोग से जीएसटी, स्टैम्प, पंजीकरण, आबकारी, खनन, ऊर्जा तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता आई है।

राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास कर टैक्स और नॉन टैक्स श्रेणियों में संरचनात्मक सुधारों को अमल में लाया गया, डिजिटल मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई तथा डेटा के आधार पर कार्य योजनाएं बनाई गई। इसी का परिणाम है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने टैक्स एवं नॉन-टैक्स दोनों श्रेणियों में व्यापक सुधार करते हुए डिजिटल निगरानी और डेटा एनालिटिक्स का प्रभावी उपयोग किया है। इसके साथ ही फर्जी बिलिंग, अवैध खनन तथा अन्य राजस्व लीकेज गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया गया है। इन प्रयासों से राजस्थान के राजस्व संग्रह में निरंतर और मजबूत वृद्धि संभव हुई है। प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 14 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है।

विभाग द्वारा रेवेन्यू इंटेलीजेंस आधारित विश्लेषण को सुदृढ़ कर 45 से अधिक डेटा ड्रिवन रिपोर्ट्स तैयार की गई, जिनसे फर्जी बिलिंग की पहचान संभव हुई और इस पर प्रभावी रोक लगी। इसके अतिरिक्त ई-वे बिल मिलान, रिटर्न प्रोफाइलिंग तथा आधुनिक आईटी टूल्स के माध्यम से हाई रिस्क करदाताओं की निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

पिछले दो वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री पर नियंत्रण के लिए इंटेलिजेंस आधारित सघन अभियान चलाए गए हैं। इन कार्रवाईयों के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब की जब्ती और अवैध भट्टियां को नष्ट कर तस्कर गिरोहों पर कठोर कार्रवाई की गई, जिससे राजस्व लीकेज को प्रभावी रूप से रोका गया।

राज्य सरकार द्वारा तकनीकी सुधारों को अपनाते हुए ई-एक्साइज प्रणाली, क्यूआर आधारित ट्रैकिंग, डिजिटल परमिट सिस्टम और एंड-टू-एंड सप्लाई चेन मॉनिटरिंग को लागू किया।शराब दुकानों के आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को खत्म करते हुए ई-लॉटरी प्रणाली को अपनाया गया है। इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनी है।

राज्य में स्टांप एवं पंजीकरण में डिजिटल सुधारों के प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ई-पंजीयन, ई-ग्रास, राज स्टाम्प और 181 हेल्पडेस्क जैसी ऑनलाइन प्रणालियों के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाया गया है। इससे नागरिकों के समय और लागत दोनों की बचत हुई है। गत दो वर्षों में विभाग द्वारा 50 लाख से अधिक दस्तावेजों का पंजीकरण किया गया है, जिससे 20 हजार 599 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही परिवार में संपत्ति हस्तांतरण, महिलाओं के नाम संयुक्त रजिस्ट्री, छोटे फ्लैटों की खरीद, टीडीआर और डेबट असाइनमेंट पर स्टांप ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की गई है।

जयपुर के नगेंद्र शर्मा सीआईएसएफ में डीआईजी बने

जयपुर। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर जयपुर निवासी नगेंद्र शर्मा को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में वरिष्ठ कमांडेंट से पदोन्नत कर उपमहानिरीक्षक बनाया गया है। यूपीएससी 2004 बैच में चयनित नगेंद्र शर्मा ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कई राज्यों और संवेदनशील स्थानो पर अपनी सेवाएं दी है। वर्तमान में नगेंद्र शर्मा प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं एनडीआरएफ में दे रहे हैं और भुवनेश्वर में पदस्थापित हैं और आपदा के प्रति संवेदनशील उडीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य से संबंधित आपदा प्रबंधन का दायित्व देख रहे है। वर्ष 2024 में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के मद्देनजर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक भी प्रदान किया गया है।

कांग्रेस ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 2 साल में हमने इतने काम कर दिए जितने कांग्रेस ने पांच साल में भी नहीं किए। जब मैं कांग्रेस के लोगों को इन कामों को बताता हूं तो इनको दिखता नहीं है और कहते हैं कि विकास कहां है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। क्योंकि उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और आंखें मूंद रखी हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने का कांग्रेस का काम है। अगर आपके पास आंकडे हैं तो बताइए आपने कितना काम किया और हमने कितना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर विद्यालय में आंखों के कैम्प लगवा रही है जिसमें आंखों की जांच भी होगी और चश्मा भी मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि वो भी इन शिविरों में जाएं और आंखों की जांच कराएं, आवश्यकता होने पर चश्मा भी लें जिससे उनको दो साल का विकास दिख जाएगा।

- जालौर की जनसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने ली कांग्रेस पर चुटकी ली
- हम विद्यालयों में लगवा रहे हैं कैम्प, कांग्रेसी इनमें जाएं और आंखों की जांच कराएं : मुख्यमंत्री

नेशनल हैराल्ड मामले में ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, धक्का-मुक्की में कई घायल

जयपुर (कासं)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के विरुद्ध प्रदर्शन किया। भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च का आव्हान किया गया था, परंतु पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड लगाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की होती रही। जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कर रहे थे। कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए शहीद स्मारक पहुंचे। जहां बैरिकेड्स पार करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए। धक्का-मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ विधायक मनीष यादव का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर गए।

- आधे घंटे के हंगामे के बाद डोटासरा व जूली के साथ कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, मनीष यादव, विद्याधर चौधरी, पूर्व विधायक गोपाल मीणा, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सभी को बसों में भरकर विद्याधर नगर थाने ले जाया गया। जहां कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। प्रदर्शन से पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लंबी पूछताछ की गई। लेकिन अदालत ने ईडी की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया। जिससे सच्चाई सामने आ गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अदालत के फैसले से यह साबित हो गया है कि ईडी राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी। उन्होंने इसे सत्य की जीत और सरकार के लिए करारा जवाब बताया।

प्रतर्वन निदेशालय के कथित दुरूपयोग के आरोप के साथ भाजपा मुख्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जयपुर में शहीद स्मारक पर रोका।

मुख्यमंत्री हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव का आज करेंगे शुभारंभ

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) द्वारा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को जयपुर स्थित होटल मैरियट में इस कॉनक्लेव का शुभारंभ करेंगे। शर्मा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव में राजस्थान की हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन व 'मेरी लाइफ-सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरमेंट' पोस्टर का विमोचन करेंगे। इस दौरान संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आनंद कुमार व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने गत दो वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण एवं ईज ऑफ डूइंग के लिए विभिन्न उत्कृष्ट कार्य किए है। उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सम्मति संचालन तंत्र में ऑटो-रिन्यूअल सुविधा की शुरूआत की गई है।

कांग्रेस केवल सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही : जोगाराम पटेल

- कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ, जनता राष्ट्रिवरोधी राजनीति को भलीभांति समझ चुकी : बालमुकुंदाचार्य

जयपुर (कासं)। संसदीय कार्य, विधि एवं न्यायिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कांग्रेसी नेताओं पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और यह अधिकार होना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस अधिकार का दुरुपयोग कर केवल सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस का आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप रहा और जयपुर में किया गया प्रदर्शन भी केवल समाचार पत्रों में जगह पाने की कोशिश भर था।

पटेल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस, भाजपा सरकार की 'राइजिंग राजस्थान' पहल पर भी अनावश्यक सवाल उठा रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस में साहस है तो वह 'राइजिंग राजस्थान' के तहत हुए कार्यों और निवेश प्रस्तावों का खंडन करके दिखाए।

नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर बोलते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चार्जशीट में तकनीकी कमियां हैं। न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा कि जांच एजेंसी के आरोप गलत हैं। कोर्ट ने केवल यह कहा है कि चार्जशीट में जो कमियां हैं, उन्हें विधि अनुसार पूरा किया जाए। इसका अर्थ यह है कि संबंधित लोग न तो आरोपों से मुक्त हुए हैं और न ही मामला समाप्त हुआ है।

भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य महाराज ने कहा कि कांग्रेस का हालिया प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ है। जनता अब कांग्रेस की नकारात्मक, भ्रम फैलाने वाली और राष्ट्रिवरोधी राजनीति को भली-भांति समझ चुकी है। कांग्रेस को यह भय सताने लगा है कि उसका राजनीतिक अस्तित्व अब समाप्ति की ओर है। इसी डर के कारण कांग्रेस कभी ईवीएम पर सवाल उठाती है, कभी वोटर लिस्ट को दोष देती है और अब तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है, जो लोकतंत्र का अपमान है।

सार-समाचार

डॉ अनीश कुमार को गोल्ड मेडल

उदयपुर, (कासं)। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से एम.एस. (जनरल सर्जरी) में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए डॉ. अनीश कुमार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित उपलब्धि उन्हें उनकी कडी मेहनत, अनुशासन और निरंतर समर्पण के लिए प्रदान की गई। वर्तमान में डॉ. अनीश कुमार गीतांजली मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उदयपुर में जनरल सर्जरी विभाग में सीनियर रेजडिंट के रूप में कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार, बल्कि उनके गुरुजनों, सहकर्मियों और पूरे चिकित्सा समुदाय में हर्ष का माहौल है। डॉ. अनीश कुमार की यह उपलब्धि गीतांजली मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की शैक्षणिक गुणवत्ता और उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा परंपरा को भी दर्शाती है।

फैक्ट्री से सामान चोरी

उदयपुर, (कासं)। ऋषभदेव थाना क्षैत्र में स्थित मार्बल फैक्ट्री से चोर कॉपर व अन्य सामान चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित अविनाश पुत्र रोशन भाणावत निवासी पाटुना चौक ऋषभदेव ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि 12 दिसंबर रात में आए चोर कानुवाड़ा हाईवे 48 पर स्थित अशोक भाणावत मार्बल फेक्ट्री में घुस कर चोर कॉपर, स्क्रेप व इनवटर बेटरियां चुरा ले गए। इसका पता चलने पर पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

कार चोरी

उदयपुर, (कासं)। शहर के बडगांव थाना क्षैत्र से चोर पीडित की कार चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित देवेन्द्र खटीक पुत्र मिठालाल निवासी गोगुंदा खारियों का मोहल्ला हॉल विद्याभवन स्कूल के सामने ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि15दिसंबर को रामगिरही में कार खड़ी की थी। जिसे अज्ञात चोर चुरा ले गया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

युवक ने की आत्महत्या

उदयपुर, (कासं)। मामा के घर आए भाणेज ने पेड़ पर फांसी लगा ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित मारूवास घासा कुण्डाल हॉल निवासी प्रहलादसिंह पुत्र शंभूसिंह ने पेड़ पर फांसी लगा आत्महत्या कर ली। प्रहलादसिंह16दिसंबर को अपने मामा कुण्डाल निवासी प्रेमसिंह के यहां मेहमान आया था। जिसने बुधवार सवेरे मामा के मकान के पिछवाडे में स्थित पेड़ पर फांसी लगा आत्महत्या कर ली। इसका पता चलने पर एएसआई महावीरसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया।

हादसे में टेम्पो चालक की मौत

उदयपुर, (कासं)। डबोक थाना क्षैत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो चालक की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16दिसंबर रात में डबोक थाना क्षैत्र रूपिज रिसोर्ट के सामने अज्ञात वाहन ने टेंपो को टक्कर मार दी। हादसे में चालक मुर्शीदनगर सविना निवासी मंजुम (44) पुत्र अहमद की मौत हो गई।इसकी सूचना मिलने पर हेडकांस्टेबल भेरूलाल ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में मंजूम के पुत्र अली ने मृत्यु पर शंका व्यक्त करते हुए जांच कराने की रिपोर्ट दी है।

मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। झाड़ोल थानाधिकारी फैलीराम ने13 जून को रात में मुंशीलाल पुत्र भेराजी निवासी चतरपुरा के घर में घुस कर मारपीट करने के मामले में फरार ईश्वरलाल पुत्र लालुराम निवासी चतरपुरा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने घटना वाली रात में नकाबपोश आरोपी व साथियों ने घर में घुस कर मुशीलाल पर हमला कर दिया था।

छात्रवृत्ति के लिए ओटीपी अनिवार्य

बांसवाड़ा। छात्रवृत्ति पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। विद्यार्थियों को वन टाइम राजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थी को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट अथवा एनएसओई ओटीआर एप के माध्यम से वन टाइम रजिस्टेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए विद्यार्थी को एनएसओई ओटीआर एप एवं आधार फेस आरडी एप डाउनलोड कर ई-केवाईसी एवं फेस ओथेन्टिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विद्यार्थी को बैंक से सम्पर्क कर बैंक खाते को आधार सीडेट एवं डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर ;क्ठज्द्ध करवाना अनिवार्य होगा। प्राचार्य डॉ. सरला पाण्डया ने बाताया कि यदि विद्यार्थी वनटाइम रजिस्ट्रेशन नही करा पाता है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुडी सभी छात्रवृत्तियां आगे प्रोसेस नही हो पाएगी।

विकास रथों से हो रहा व्यापक प्रचार

बांसवाड़ा। राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के पांचों विधानसभावार संचालित एलईडी वैन विकास रथों के माध्यम से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इन विकास रथों द्वारा आमजन को सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। गुरुवार को घाटोल विधानसभा क्षेत्र के मुडासेल, मियासा, पाडला, वाडगुन, भुगंड़ा पहुंचेंगे। इसी प्रकार बागीदौरा विधानसभा के भलेर भोदर, चोरड़ी, सुन्दराव, कड़दा, बोरवनिया, चादरवाड़ा, कानेला में, बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बोरिया, पलसवानी, गनाऊ, झूपेल, लिमथान में। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़, बगायचा, काकनवानी, वसुनी, बिलीपाड़ा, उन्कला, डूंगरी पाड़ा में, गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के कोटडा बड़ा, पालोदा, लसाड़ा, रोहिडा, सुंदनी, मेयावास में प्रचार प्रसार किया जाएगा।

शिविर में मिला मकान का पट्टा

डूंगरपुर। शहरी समस्या समाधान शिविर में आमजन को रियायती दर में अपने आवास का प्रमाण पत्र मिल रहा है। बुधवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड मुख्य अतिथि के पद पर शामिल हुए। शिविर में अध्यक्षता सभापति अमृत कलासुआ और विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री मिथलेश गौतम भाजपा संभाग प्रभारी महेंद्रजित सिंह मालवीया उपसभापति सुदर्शन जैन थे। आयुक्त प्रकाश डूडी ने शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए पिछले तीन माह में परिषद् की और से से पट्टे वितरित कर लाभान्वित किया है। सभापति अमृत कलासुआ ने कहा की शहर के बीजेपी बोर्ड ने आमजन की तकलीफ को समजते हुए विकास के कार्य किये है 36० परिवारों को मुख्यमंत्री जन आवास में फ्लेट दिए है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शहरी विकास एवं स्व.शासन विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा के अथक प्रयास से सारे कार्य ऑनलाइन हो रहे है ऐसे में फाइलों को लेकर आमजन को इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है नगर परिषद् की और से फोन कर के आमजन को बुलाकर पट्टे और अन्य कार्य कर दस्तावेज दिए जा रहें है।

कांग्रेस ने महानरेगा नाम बदलने के विरोध में किया प्रदर्शन

उदयपुर, (कासं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बुधवार को उदयपुर देहात एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से मोदी,शाह सरकार द्वारा ईडी व अन्य संवैधानिक संस्थानों के दुरूपयोग एवं मनरेगा का नाम परिवर्तन कर योजना को कमजोर करने के कुप्रयास के विरोध में जिलाधीश कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया।

उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ संजीव राजपुरोहित ने बताया कि पिछले एक दशक से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश की संवैधानिक संस्थाओ के दुरूपयोग कर कांग्रेस नेतृत्व विशेषकर सोनिया गांधी एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बदनाम करने की निरन्तर कोशिशों के बावजूद नेशनल हेराल्ड मामले में न्यायालय द्वारा ईडी की शिकायतों को खारिज करना मोदी सरकार की बदनियती और कुंठा को उजागर करता है,साथ ही मनरेगा जैसी महत्ती योजना का नाम बदल कर उसे कमजोर करने के कुप्रयास के विरोध में एआईसीसी एवं पीसीसी के निर्देशानुसार उदयपुर देहात एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि मोदी.शाह की सरकार ईडी और अन्य संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। माननीय न्यायालय की ओर से श्रीमती सोनिया गांधी एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर लगाए गए झूठे मुकदमों को खारिज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाई है। जो साफ इशारा करता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ईडी व अन्य संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सत्ता और एजेंसियों के दुरुपयोग पर सत्य की जीत है।न्यायालय द्वारा सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज किया जाना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई अपराध था ही नहीं। इस निर्णय ने मोदी सरकार की बदनीयती और गैर कानूनी कार्रवाई को बेनकाब कर दिया। आज माननीय न्यायालय ने इस षड्यंत्र पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि अंततः जीत सत्य और न्याय की होती है।

मीणा ने महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर भी विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा एवं आरएसएस हमेशा से ही महात्मा गांधी के विरोधी रहे है। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर इस बात को प्रमाणित कर दिया कि वे सिर्फ राष्ट पिता महात्मा गांधी का नाम उपयोग कर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते है। मनरेगा केवल एक योजना नहींए बल्कि करोडों गरीबों के लिए रोजगार का कानूनी अधिकार है। महात्मा गांधी जी के नाम से जुडी इस योजना को कमजोर करनाए उसका नाम मिटाने की कोशिश करना गरीबों के अधिकार और बापू के विचारों पर प्रहार है। मोदी सरकार मनरेगा को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेकर गरीब की रोजी रोटी खत्म करना चाहती हैं। कुल मिलकर मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करने का कुप्रयास कर रही है।

उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड ने कहा कि माननीय न्यायालय के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस नेतृत्वए विशेषकर श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध यंग इंडियन मामले में की गई ईडी की कार्रवाई पूरी तरह अवैध,दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थी। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि ईडी का यह मामला न तो उसके क्षेत्राधिकार में आता है और न ही इसके लिए कोई वैध एफआईआर मौजूद है। ऐसे में यह कार्रवाई कानून के नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण थी। पिछले एक दशक से मोदी सरकार जिस तरह देश के सबसे बडे विपक्षी दल और गांधी परिवार को बदले की राजनीति का शिकार बना रही थी, वह आज देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। राठौड ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कहा कि मोदी सरकार की नियत में खोट है वो राष्ट पिता महात्मा गांधी जी के नाम को भी मिटाना चाहती है लेकिन कांग्रेस पार्टी और देश का लोकतंत्र ऐसा कभी नहीं होने देगा। विरोध प्रदर्शन के बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन भी किया।

विरोध प्रदर्शन में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा,उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड,लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा,पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत,पूर्व मंत्री डॉ मांगी लाल गरासिया,पीसीसी उपाध्यक्ष सुरेश श्रीमाली, पूर्व मंत्री एवं प्रदेश इंटक अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, पीसीसी महासचिव लाल सिंह झाला,गोपाल शर्मा,पंकज शर्मा,सुरेश सुथार,पीसीसी सचिव दिनेश श्रीमाली,भीम सिंह चुंडावत,अरुण टांक,पूर्व उप जिला प्रमुख लक्ष्मी नारायण पंड्याए डॉ कौशल नागदा,दिनेश दवे,दलपत सिंह चुंडावत, मोहम्मद अय्यूब ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंहए गुलाब सिंह राव आदि मौजूद रहे।

बुजुर्ग ने फंदा लगा दी जान

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के गलन्दर गांव में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग ने अपने घर के पास खेत में पेड से फँदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार रात खाना खाने के बाद वह सो गया था, जिसके बाद सुबह उसका शव पेड से लटका मिला। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।

रामसागडा थानाधिकारी कैलाश पंचारिया ने बताया कि गलन्दर निवासी कमलाशंकर कटारा ने इस संबंध में रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार रात उसके पिता कचरू कटारा ने परिवार के साथ खाना खाया और सो गए थे।

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगपालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द

सं. 15628 दिनांक: 16.12.2025

-: लोक सूचना :-

श्री चतरलाल गमेती पिता श्री जेताजी भील निवासी श्रीनाथ कॉलोनी, धोला मंगरा, नाथद्वारा तहसील-नाथद्वारा जिला-राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात् -

क्र. सं.	तहसील का नाम जिले सहित	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1.	नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	नाथद्वारा	4526/3156, 4530/967, 4537/970, 4540/971	रकबा 0.1745 हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 16.12.25 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगपालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द

सं. 15636 दिनांक: 16.12.2025

-: लोक सूचना :-

श्री लेहरूलाल मीणा पिता श्री जेताजी भील निवासी श्रीनाथ कॉलोनी, धोली मंगरा, नाथद्वारा तहसील-नाथद्वारा जिला-राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात् -

क्र. सं.	तहसील का नाम जिले सहित	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1.	नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	नाथद्वारा	3157/972, 3158/972, 4525/3156, 4529/967, 4536/970, 4539/971, 972	रकबा 0.1744 हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 16.12.25 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

सांसद की केंद्रीय रेल मंत्री से शिष्टाचार भेंट

राजसमंद। सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर राजसमंद संसदीय क्षेत्र में रेलवे से जुडे विकास कार्यों एवं यात्री सुविधाओं को लेकर विस्तृत और सार्थक चर्चा की गई।सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने मंत्री के समक्ष राजसमंद से मुंबई तक नई रेल सेवा प्रारंभ करने, क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव सुनिश्चित करने तथा यात्रियों की सुविधा बढाने से जुडे विषयों को प्रमुखता से रखा।

हर सिलेंडर से तीन किलो गैस कम निकली

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर में गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले हॉकर से जब उपभोक्ता के घर सिलेंडर लिए और अपने कांटे से वजन कराया तो प्रत्येक सिलेंडर में तीन.तीन किलो गैस कम मिली। बाद में डीएसओ की टीम को सूचना दी तो टीम मौके पर पहुंची। इस बीच हॉकर दो सिलेंडर बाइक पर लेकर भाग गया।

राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समिति के संभाग अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह शेखावत ने यह कार्रवाई डीएसओ की टीम को बुलाकर की। शेखावत ने बताया कि शहर के एनबी नगर धाऊजी की बावडी निवासी राजन गुप्ता पिछले एक साल से गैस की टंकी में कम वजन आने से परेशान थे।शेखावत ने बताया कि इस चोरी को पकडने के लिए शेखावत और गुप्ता ने प्लान बनाया। इसके तहत मेवाड जावा गैस एजेंसी के हॉकर रिंकू को फोन कर गुप्ता ने पारिवारिक समारोह बताते हुए 5 गैस सिलेंडर मंगवाए।हॉकर मंगलवार को ये सिलेंडर लेकर आया। वहां अपने कांटे से वजन कर बताया कि सिलेंडर पूरे भरे हुए। इस बीच वहां पहुंचे शेखावत ने अपने कांटे से वजन किया तो सभी सिलेंडर में करीब 3 किलो गैस कम निकली।शेखावत ने रसद विभाग को सूचना दी जिस पर मौका देखकर हॉकर दो टंकी लेकर बाइक से भाग गया। मौके पर आई रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी डॉ निशा मूंदडा व मानसी पंड्या ने तीनों सिलेंडर का कांटा कराया तो प्रत्येक में करीब 2 किलो 800 ग्राम गैस कम मिली।शेखावत ने बताया कि मौके पर टीम ने गैस एजेंसी के प्रबन्धक विकास जावा को बुलाया व उनके बयान भी लिए। मौका पर्चा बनाकर तीनों सिलेंडर टीम ने जब्त कर लिए।

कार्यालय नगरपरिषद निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक:-नपनि/हस्ता./157331/2025-26/5231-33 दिनांक:-18.11.2025

-: आपत्ति सुचना :-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा आवासीय रूपान्तरण पट्टा विलेख सं. 56/2013-14 दिनांक 27.12.2013 से राजस्व ग्राम निम्बाहेड़ा की आराजी सं. 3580/856 में से 1368 वर्गफीट आवासीय रूपान्तरण कर पट्टा विलेख श्री खेमा पिता श्री उंकार माली निवासी निम्बाहेड़ा के नाम जारी किया गया। मूल आवंटी/पट्टाधारी की मृत्यू दिनांक 19.04.2013 एवं मूल अवंटी की धर्मपत्नी श्रीमती नन्दू बाई की मृत्यू दिनांक 26.05.2014 को गया। आवेदक श्री किशनलाल माली पिता श्री खेमराज माली द्वारा आवेदन प्रस्तुत उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड के चैन दस्तावेज प्रस्तुत कर हस्तान्तरण अपने नाम से किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अत: इस संबंध में किसी आस-पड़ौस/परिवार जन या किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो मय सबुत के अन्दर मियाद आपत्ति प्रकाशन से 07 दिवस में नगर परिषद निम्बाहेड़ा में, कार्यालय दिवस में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद समयावधि कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी, और आवेदक श्री किशनलाल पिता श्री खेमा जो निवासी बापू बस्ती निम्बाहेड़ा के नाम से हस्तान्तरण कि कार्यवाही प्रस्तावित कि जाकर आवेदक के पक्ष में हस्तान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। सूचित हो।

आयुक्त नगर परिषद निम्बाहेडा

जिला स्तरीय प्रदर्शनी: विकास की झलक से हुए रूबरू

उदयपुर, (कासं)। राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के तत्वावधान में सूचना केंद्र परिसर में आयोजित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी को लेकर आमजन में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनी के दूसरे दिन बुधवार को बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों एवं शहरवासियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों, नवाचारों तथा जनहित में किए गए निर्णयों को आकर्षक पैनल, चार्ट, बैनर एवं डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रदर्शित किया गया है। युवाओं और विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी में दर्शाई गई योजनाओं को न केवल रुचि के साथ देखा, बल्कि उनके उद्देश्य, लाभ एवं पात्रता संबंधी जानकारी भी प्राप्त की।

प्रदर्शनी का अवलोकन करने आए विद्यार्थियों ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं और विकास की दिशा को समझने का अवसर मिलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह प्रदर्शनी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। इसमें राज्य सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मिल पा रही है। युवाओं ने रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, महिला एवं युवा सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं में विशेष रुचि दिखाई। उपनिदेशक जनसम्पर्क गौरीकान्त शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना और नागरिकों को योजनाओं से जोड़ना है, ताकि वे इनका अधिकतम लाभ उठा सकें। यह जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी 18 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है तथा प्रतिदिन प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक आमजन के अवलोकन के लिए खुली रहेगी।

अतिक्रमण हटाए

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के ऋषभदेव में स्थानीय प्रशासन ने नए बस स्टैण्ड और बाजार में बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। देवस्थान विभाग, ग्राम पंचायत, तहसील और पटवार मंडल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सडक किनारे और सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया।

कार्रवाई के दौरान खेरवाडा के पूर्व विधायक नानालाल अहारी के विरोध के बाद गहमागहमी की स्थिति बन गई। अहारी ने बिना किसी पूर्व सूचना के ठेले वालों को हटाने को लेकर नाराजगी जताई। अहारी ने कार्रवाई को एकतरफा बताया। अधिकारियों का कहना था कि अतिक्रमण से जाम की स्थिति लगने के कारण यह कार्रवाई की गई।

उदयपुर के ऋषभदेव में स्थानीय प्रशासन ने नए बस स्टैण्ड और बाजार में बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया।

कार्यालय नगरपरिषद निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक:- नपनि/हस्ता./161815/2025-26/5811-5813 दिनांक:- 10.12.2025

-: आपत्ति सुचना :-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि नगरपालिका निम्बाहेड़ा के आर्दश कॉलोनी आई.यू.डी.पी. स्कीम के तहत आवंटीत भूखण्ड सं. 121 साईज (30'x64'=1920 sqf) का पट्टा विलेख/पत्रावली 56/1996-97 दिनांक 10.03.1997 का पट्टा श्री अनिल कुमार पिता श्री भजनलाल जिज्ञासू निवासी निम्बाहेड़ा के नाम जारी किया गया। मूल आवंटी/पट्टाधारी द्वारा आवंटी भूखण्ड में से भूखण्ड साईज (24'x64'=1280 sqf) भूखण्ड को जरीये विक्रय विलेख से श्री कन्हैयालाल पिता श्री भोजराज जी दातवानी निवासी निम्बाहेड़ा को विक्रय किया गया। क्रेता श्री कन्हैयालाल पिता श्री भोजराज जी दातवानी निवासी निम्बाहेड़ा का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2025 को हो जाने से उनके वारिसानों में पूनम दातवानी (पत्नी), दीपक दातवानी (पूत्र), भावना दातवानी (पुत्री), उक्त वारीसानों में से पुत्री भावना दातवानी द्वारा अपना हकत्याग कर पूनम दातवानी एवं दीपक दातवानी के पक्ष में हक त्याग किया है। अत: हकग्रहिता श्रीमती पूनम दातवानी पत्नि स्व. श्री कन्हैयालाल एवं दीपक दातवानी पिता स्व. श्री कन्हैयालाल निवासी निम्बाहेड़ा द्वारा भूखण्ड के चैन दस्तावेज प्रस्तुत कर हस्तान्तरण अपने नाम से किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अत: इस संबंध में किसी आस-पड़ौस/परिवार जन या किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो मय सबुत के अन्दर मियाद 07 दिवस में नगर परिषद निम्बाहेड़ा में, कार्यालय दिवस में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद समयावधि कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी, और आवेदक श्रीमती पूनम दातवानी पत्नि स्व. श्री कन्हैयालाल एवं दीपक दातवानी पिता स्व. श्री कन्हैयालाल निवासी निम्बाहेड़ा के नाम से हस्तान्तरण कि कार्यवाही प्रस्तावित कि जाकर आवेदक के पक्ष में हस्तान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। "सूचित हो"

आयुक्त नगर परिषद निम्बाहेडा

रावल तहसीलदार पद पर पदोन्नत

उदयपुर,(कासं)। जिला कलक्टर कार्यालय की राजस्व शाखा के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत जितेश रावल की तहसीलदार पद पर पदोन्नति हुई। इस पर जिला कलक्टर नमित मेहता ने श्री रावल को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की। कार्यक्रम के दौरान रेवेन्यू कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चुंडावत भी उपस्थित रहे।

खमनोर व देलवाड़ा में ब्लॉक स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित

राजसमंद। खमनोर एवं देलवाडा ब्लॉक में विभागीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक उदयपुर डॉ. प्रकाश चन्द्र शर्मा, सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश मीणा, डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण डॉ. महेन्द्र सिंह खंगारोत पहुंचे तथा विभाग अन्तर्गत संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की गांव वार समीक्षा की।

सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल ने निर्देशित किया कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिये 3० वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की स्क्रीनिंग तथा फॉलोअप में तेजी लाये साथ ही शत प्रतिशत लोगों की आभा आईडी बनाकर, पोर्टल से सम्बद्ध करें। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग तथा निक्षय पोषण योजना के तहत शत-प्रतिशत लाभार्थीयो का बैंक विवरण पोर्टल पर दर्ज करने के लिये निर्देशित किया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश मीणा ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की।

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

Email: np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/उप.एकी./2025/15721 दिनांक: 17.12.2025

- : आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुद्वा/पट्टा शुद्वा के आधार पर भूखण्डों का उपविभाजन/एकीकरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर उपविभाजन/एकीकरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति कापता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्रीमती भागवन्ती गोस्वामी पत्नि श्री गुरू गोविन्द भारती निवासी-मोहनगढ निचला चौक, नाथद्वारा जिला- राजसंमद	भूखण्ड संख्या-16 बी, क्षैत्रफल-1250 वर्गफिट, कृष्णा फेज-1 आवासीय कॉलोनी, भलावतों का खेडा, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-15 व 16 ए	30 फिट रोड	30 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-17
		भूखण्ड संख्या- 15 व 16 ए, क्षैत्रफल-3750 वर्गफिट, कृष्णा फेज-1 आवासीय कॉलोनी भलावतो का खेडा, नाथद्वारा	30 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-16 बी	30 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-14 व 17

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F7() B.PLAN/MISC/2025-26/1831 **आम-सूचना** दिनांक: 19.11.2025

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां(Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता में समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना में निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/ योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1.	श्रीमती सीमा कावडिया पत्नी श्री विमल कुमार कावडिया	सुखेर	1592 से 1599	11-ए	4585.88 वर्गफीट	चित्रकुट नगर योजना में स्थित इएसआईसी हॉस्पिटल के सामने वाली 80 फीट सडक पर सक्सेस कोंचिंग क्लासेस के सामने स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.11( )Regin-III/2025/6861 **आम-सूचना** Date: 16/12/25

निम्नानुसार आवेदक द्वारा सारणी में वर्णित राजस्व ग्राम एवं खसरा नम्बर की भूमि का आवंटन/नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	आवेदक का नाम /पिता का नाम
1	बेडवास	1718 से 1727	12 And 14	3841.5	श्रीमती बसन्ती देवी सुहेल पत्नी श्री शान्तिलाल, श्री शान्तिलाल सुहेल पिता श्री देवीलाल जी

अतः उपरोक्तानुसार आवेदित भूखण्डो का आवंटन/लीजड़ीड आवेदक के नाम करने के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति/ऐतराज होतो इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मियाद गुजरने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(शैलेश खैरवा) प्राधिकृत अधिकारी
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

गांव-गांव पहुंचे विकास रथ

डूंगरपुर, (निसं)। राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चारों विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ यात्रा गांव-गांव पहुंच कर योजनाओं, विकासात्मक कार्यो की जानकारी प्रदान कर रही है। इसके साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जयपुर द्वारा प्रकाशित जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार साहित्य भी वितरण किया जा रहा है।

विकास रथ यात्रा (एलईडी वेन) द्वारा विकासात्मक कार्यो, उपलब्धियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही ग्रामवासी भी उत्साह से सम्मिलित हो रहें है। बुधवार को विधानसभा क्षेत्र सागवाडा में विकास रथ नगरपालिका सागवाडा, सरोदा, बरबोदिया, विधानसभा चौरासी में करावाडा, भंडारी,विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में गोकुलपुरा, वागदरी, जालुकुंआ, विधानसभा क्षेत्र आसपुर में दामडी, खलील, आसपुर में रथ यात्रा पहुंची जहां ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया।

विधानसभा क्षेत्र सागवाडा का विकास रथ भू-अभिलेख वृत सागवाडा के ग्रामीण सेवा फोलोअप शिविर में पहुंचा। शिविर में बतौर अतिथि पूर्व सांसद कनकमल कटारा, नगर पालिका अध्यक्ष आशीष जैन, उपखण्ड अधिकारी सुबोध चारण, विकास अधिकारी हीराराम मेघवाल, अधिशासी अधिकारी सुहेल शेख, वनोरी और आरा के सरपंच और सभी पार्षद मौजूद रहें। जिसमे ग्राम पंचायत वनोरी के देवीलाल पिता धुला डामोर, भरत पिता काला डामोर, रूपा पिता काला डामोर, पंकज पिता कलाजी डामोर, कपिल पिता कलाजी डामोर को आवासीय पट्टा वितरण कर लाभांवित किया गया ।

इस अवसर पर पूर्व सांसद कनकमल कटारा एवं अन्य अतिथियों ने सरकार के 2 वर्ष में किए गए विकासात्मक कार्यो, उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए विभिन्न योजना अंतर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इसीक्रम में बरबोदनिया में विकास रथ के पहुंचने पर समाजसेवी महेंद्रसिंह पंवार, गोपाल फलोत, दिनेश प्रजापत, कालूराम पाटीदार, महेंद्र पुंजोत, भारत सिंह अहाडा,सरपंच महेंद्र सरपोटा उपसरपंच गोविन्द पुंजोत , ग्राम पंचायत सरोदा में सरपंच पन्नालाल डोंडीयार, समाजसेवी भारतेन्दु व्यास, वार्ड पंच वजेंग पाटीदार, जितेंद्र व्यास, लालू ननोमा, कविश जोशी के साथ बडी संख्या में मौजूद ग्राम वासियों ने विकास रथ का स्वागत किया तथा विकासात्मक कार्यो एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एलईडी के माध्यम से ली। ओबरी तहसीलदार रक्षा बुनकर ने संध्या देवी पत्नी हरिओम पुंजोत और मणी देवी पत्नी धनालाल खराडी को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से लाभान्वित किया। राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को ग्राम पंचायत गोकुलपुरा में ग्रामीण सेवा शिविर फॉलोअप कैम्प रखा गया। जिसमें पांच ग्राम पंचायत गोकुलपुरा, भाटपुरा, माथुगामडा खास, माथुगामडा पाल एवं मैताली और इनके 1० राजस्व गांव शिविर में उपस्थित रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत पलासमा, पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- /पंचा/2025-26/362 दिनांक: 12.12.25

-ः ई निविदा सूचना- 80/2025-26 :-

इस ग्राम पंचायत में DMFT योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य रा.उ.मा.वि. पलासमा दो कमरे निर्माण कार्य हेतु UBN No ZUD2526WSOB03010 के माध्यम से ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajathan.gov.in पर देखी जा सकती है।

प्रशासक
ग्राम पंचायत पलासमा
पं.स. सायरा जिला उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पलासमा
पं.स. सायरा जिला उदयपुर (राज.)

चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी एक मौका चूक गई। ग्रीन को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी ने रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए।- **आर अश्विन**

पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, कैमरन ग्रीन को लेकर बोलते हुए।

आज का खिलाड़ी — **लियोनेल मेस्सी**

अर्जेंटीना- के फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने अपने इंडिया टूर के समापन के बाद भारत के प्यार और स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। इस टूर में खूब मस्ती हुई और कुछ यादगार क्रॉसओवर पूरे देश में ट्रेंड कर रहे थे। अपने इंस्टाग्राम पर मेस्सी ने लिखा, ''नमस्ते भारत! दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की यात्राएं अविश्वसनीय रहीं। गर्मजोशी से स्वागत, शानदार आतिथ्य और पूरे दौरे के दौरान मिले प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है!''

क्या आप जानते हैं ?... विराट कोहली की 2025 में उल्लेखनीय निरंतरता ने उन्हें भारत के सर्वोच्च वनडे रन-स्कोरर का खिताब दिलाया, उन्होंने 651 रनों के प्रभावशाली स्कोर के साथ वर्ष का समापन किया।

राजस्थान ने नागर हवली दमन दयू को 6-0 से हराया

जयपुर, 17 दिसम्बर। राजस्थान ने 6-0 से की विजय शुरुआत करते हुए विद्याधर नगर स्टेडियम मे प्रारम्भ हुई सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आगाज किया। पहले दिन 2 मैच खेले गए प्रथम मैच गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य खेला गया जिसमे गुजरात ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुऐ 3-0 से मैच जीता! मैच के 8वे एवं 78 वे मिनट मे गुजरात के मोईनुद्दीन ने गोल किया इसके बाद मैच के 89 वे मिनट मे धर्मेश से गोल करे के टीम को 3-0 से विजय बनाया। दूसरा एवं उद्घाटन मैच राजस्थान और दादर और नागर हवली दमन दयू के मध्य खेला गया। मैच के दुसरे मिनट मे ही दादर नागर की टीम से आत्मघाती गोल कर राजस्थान टीम को 1-0 की बढ़ात दे दी। इसके बाद राजस्थान ने विरोधी टीम के गोल पर भरसक प्रयास किया जिसकी बदौलत मैच के 44 वे मिनट मे राजस्थान के अमित ने दमन के रक्षापक्ति को छकाते हुए शानदार गोल कर के बढ़ते को 2-0 से कर दी। मध्यन्तर तक राजस्थान ने यह बढ़त बरकरार रखी और मध्यन्तर के बाद राजस्थान ने अपना पारम्परिक अंदाज मे खेल का परिचय देते हुऐ मैच के 62 वे मिनट राजस्थान के मुकेश से शानदार बाइसाइकिल किक से गोल करे के बढ़त 3-0 कर दी। इसके बाद 72 वे मिनट मे नीरज ने और 81 वे मिनट मे मिलन और 82 वे मिनट मे मुकेश से गोलकर मैच को 6-0 से मैच अपने नाम किया। राजस्थान के मुकेश को प्लेयर ऑफ ऑफ दा मैच चुना गया।

एमसीजी और संस्कार क्रिकेट अकादमी जीती

जयपुर, 17 दिसम्बर। जयपुर कप सीजन-1 में आज के पहले मैच में केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37.2 ओवर में 240 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाएं! राज ने 46 और राकेश जांगिड़ ने 39 रनों का योगदान दिया। एमसीजीक्रिकेट अकादमी की ओर से श्रेष्ठ पंत ने 3 , मितेश जांगिड़ और नयन माली ने दो-दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमसीजीक्रिकेट अकादमी ने 27.3 ओवर में 243 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना कर जीत हासिल कर ली! पुखराज कुमार ने 104 और पंकज जांगिड़ ने 61 रनों का योगदान दिया! केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी की ओर से धर्मेंद्र यादव और राहुल सैनी ने दो-दो विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच पुखराज कुमार को चुना गया।

दूसरे मैच में संस्कार क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 38.5 ओवर में 300 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाएं। आदित्य झाला ने 65, हार्दिक ने 64 और अभिषेक यादव ने 55 रनों का योगदान दिया। कैंडलविक क्रिकेट अकादमी की ओर से मानव ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी कैंडलविक क्रिकेट अकादमी 32 ओवर में 181 रन पर ऑल आउट हो गई! मेहुल सिंह ने सर्वाधिक 59 रनों का योगदान दिया। संस्कार क्रिकेट अकादमी की ओर से अभयराज ने तीन विकेट लिए। मैच का मैन ऑफ द मैच आदित्य झाला को चुना गया।

जयपुर ने बेदला को हराया, लांस वाटसन ने डबल हैट्रिक के साथ 8 गोल किये

जयपुर, 17 दिसम्बर। पीपीसी पोलो ग्राउंड पर जयपुर पोलो टीम और बेदलाके बीच मैच खेला गया जिसमें जयपुर ने बेदला को 4.5 के मुकाबले 9 गोल से हराया। आधे गोल का एडवांटेज लेकर खेल रही बेदला पोलो टीम की ओर से सिद्धांत शर्मा ओर फ्रेडरिक ने 2-2 गोल किए। जयपुर पोलो टीम की ओर से हुर्रे अली ने 1 गोल ओर लांस वाटसन ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए डबल हैट्रिक लगाते हुए 8 गोल कर टीम को जीत दिलाई।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

नया पावर हाउस, बसनी, जोधपुर, वेबसाइट:www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl/

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 (2) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), जोधपुर (जिसे डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है) ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 64 के तहत, आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2019 (समय-समय पर संशोधित), आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2025 और आरईआरसी (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर के समायोजन, एआरआर और टैरिफ के निर्धारण और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन हेतु एक याचिका दायर की है।

याचिका की प्रतियां आयोग के कार्यालय में और निम्नलिखित स्थानों पर निरीक्षण/पठन के लिए उपलब्ध हैं और 200 रुपये के भुगतान पर खरीदी जा सकती हैं:

1. लाइसेंसधारी का मुख्यालय –न्यू पावर हाउस, बसनी, जोधपुर।
2. ओ एंड एम के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, जोधपुर सिटी सर्कल, जोधपुर जिला। सर्किल, जोधपुर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बाड़मेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/बीकानेर/चूरू/जालौर/बालोतरा/फलोदी।

यह याचिका निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। **www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl/** और आरईसी की वेबसाइट पर भी। **www.rerc.rajasthan.gov.in**

जेडीवीवीएनएल द्वारा दिनांक 24.12.2025 को सुबह 11:00 बजे जोधपुर स्थित न्यू पावर हाउस के सम्मेलन कक्ष में याचिका की ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिन प्रस्तुति में भाग ले सकते हैं।

टिप्पणी/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति सहायक विवरणों और आरईआरसी (व्यावसायिक लेनदेन) विनियम 2021 के प्रपत्र-3 में एक शपथ-पत्र के साथ छह प्रतियों में प्राप्तकर्ता अधिकारी, आरईआरसी, विनियमक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302001 के पास जमा कर सकते हैं, ताकि यह 06.01.2026 तक प्राप्तकर्ता अधिकारी तक पहुंच जाए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एआरआर, टैरिफ और निवेश योजना के समायोजन हेतु दायर याचिका के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है (याचिका संख्या 2380/25):

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के समायोजन का सारांश (रुपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	जेडीवीवीएनएल अनुमत	जेडीवीवीएनएल ट्रू अप के लिए दावा किया गया
1	आय		
2	बिजली की बिक्री	20662	20768
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए एफएसए की वसूली	1437	
4	व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	0	160
5	गैर-टैरिफ आय/अन्य टैरिफ आय (आरवीपीएन/आरवीयूएन के ट्रू-अप क्रेडिट सहित)	406	1188
6	व्हीलिंग शुल्क, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से प्राप्त आय	1	2
7	कुल राजस्व (ए)	22506	22118
8	व्यय		
9	प्रसारण शुल्क सहित बिजली खरीद लागत	16974	19995
10	संचालन एवं रखरखाव व्यय	1636	1361
11	टर्मिनल लाभ	370	1250
12	मूल्यह्रास	706	1091
13	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (उपभोक्ताओं की सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज सहित)	666	1435
14	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	249	2584
15	विनियामक परिसंपत्तियों पर ब्याज	1981	
16	यदि कोई अशोध्य ऋण माफ किया गया हो तो	0	34
17	बीमा व्यय	26	0.50
18	अन्य डेबिट (पिछली अवधि की मदों सहित)	0	(351)
19	कुल व्यय (ARR) (B)	22609	27399
20	अधिशेष/(अंतर) (C=A-B)	(103)	(5281)
21	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सब्सिडी/अनुदान		
22	धारा 65 (डी) के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा उपयुक्त सरकार से प्राप्त राजस्व सब्सिडी	26	55
23	एफआरबीएम योजना (ई) के तहत हानि अनुदान	77	2485
24	अनुदान के बाद राजस्व अधिशेष/(अंतर) (F=C+D+E)	0	(2741)
25	विलंबित भुगतान अधिभार (उपभोक्ताओं से) (जी)	0	237
26	असाधारण आय/(व्यय) (एच)	0	2789
27	शुद्ध राजस्व अधिशेष / (अंतर) (F-G+H)	0	(188)

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
1	बिजली खरीद व्यय	18123
2	संचालन एवं रखरखाव व्यय	
2.1	कर्मचारी व्यय	1373
2.2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय	169
2.3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	549
2.4	टर्मिनल लाभ	1326
3	मूल्यह्रास	1796
4	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (सुरक्षा जमा पर ब्याज सहित)	1664
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	264
6	विनियामक परिसंपत्तियों पर ब्याज	1565
7	प्रसारण शुल्क	2293
8	एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी शुल्क	12
9	यदि कोई अशोध्य ऋण माफ किया गया हो तो	-
10	कुल राजस्व व्यय	29133
11	लाभांश	-
12	आरओई पर कर	-
13	कुल राजस्व आवश्यकता	29133
14	घटाएं: गैर-टैरिफ आय	302
15	घटाएं: व्हीलिंग शुल्क से प्राप्त आय	3
16	घटाएं: क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज के मद में प्राप्त राशि	0
17	घटाएँ:व्हीलिंग के शुल्क पर अतिरिक्त अधिभार के कारण प्राप्त रसीद	0
18	खुदरा शुल्क से कुल शुद्ध राजस्व की आवश्यकता (13-14-15-16-17)	28828
19	मौजूदा टैरिफ पर बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व	23856
20	व्यापार से प्राप्त राजस्व	790
21	विनियामक अधिभार से राजस्व	2837
22	एफपीपीएएस से राजस्व	474
23	पीओसी से प्राप्त राजस्व	20
24	उपयुक्त सरकार से प्राप्त सब्सिडी (हानि सब्सिडी सहित)	2259
25	मौजूदा टैरिफ पर वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष/(अंतर) (19+20+21+22+23+24-18)	1407
26	टैरिफ युक्तिकरण के बाद बिजली की बिक्री से राजस्व	23854
28	शुल्क युक्तिकरण के बाद राजस्व में वृद्धि/(कमी)	(2)
29	टैरिफ युक्तिकरण के बाद वर्ष (25+28) के लिए अधिशेष/(अंतर)	1405

तालिका 3: राज्य सीमा अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा (एमयू)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
राज्य सीमा के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा (एमयू)	40,532

तालिका 4 वितरण हानियाँ

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
वितरण हानि (%)	13.00%

डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित निवेश योजना प्रस्तावित की है:

तालिका 5: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश योजना और वित्तपोषण के स्रोत (रुपये करोड़ में)

क्रमांक	योजना का नाम	मात्रा
1	प्रसारण एवं वितरण कार्यक्रम	1045
2	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	2044
3	आरडीएसएस (बुनियादी ढांचा)	807
4	आरडीएस (आरएमएस और आईटी/ओटी)	61
5	आरडीएसएस (छूटे हुए आरएचएच का विद्युतीकरण)	142
6	आरडीएसएस (फीडर पृथक्करण)	775
7	कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए दो ब्लॉक आपूर्ति (आरडीएसएस)	290
8	आरडीएसएस (डीए-JUGA और छुटे हुए घरेलु कनेक्शन)	250
	कुल	5414
क्रमांक	वित्तपोषण का स्रोत	
1	ऋण	2588
2	अनुदान	1395
3	हिस्सेदारी	1113
4	उपभोक्ता योगदान	318
	कुल	5414

टिप्पणी:- डिस्कॉम ने बताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग घटक के अंतर्गत व्यय 272 करोड़ रुपये है। हालांकि, पूंजी निवेश के उद्देश्य से, स्मार्ट मीटरिंग घटक के लिए आवंटित व्यय को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसे कुल व्यय (टोटेक्स) मोड पर लागू किया जाना है।

डिस्कॉम ने क्रॉस सब्सिडी शुल्क, व्हीलिंग शुल्क, अतिरिक्त अधिभार और ग्रीन टैरिफ में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव भी दिए हैं:

तालिका 6: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित क्रॉस सब्सिडी अधिभार

वर्ग	वोल्टेज (केवी)	सीएसएस (रु./किलोवाट घंटा)
व्ह्द औधोयोगिक	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
मिश्रित भार- एचटी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
अघरेलू-एचटी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75

तालिका 7: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित व्हीलिंग शुल्क

विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)
132 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.01
33 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.11
11 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.63
कम वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	2.49

तालिका 8: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार

विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)
ग्रीन टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)	0.00*

तालिका 9: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित हरित ऊर्जा शुल्क

विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)
ग्रीन टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)	0.00*

* **टिप्पणी:-** डिस्कॉम द्वारा ग्रीन पावर का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं से कोई प्रीमियम शुल्क न लेने का प्रस्ताव है। ग्रीन पावर उसी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी जो किसी विशेष श्रेणी के लिए लागू होती है।

डिस्कॉम ने याचिका में किसी भी प्रकार के शुल्क संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि, डिस्कॉम ने निम्नलिखित शुल्क युक्तिकरण उपायों की मांग की है:

1. मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एमपी/एचटी-3) के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क में कमी:-मध्यम औद्योगिक सेवा के अंतर्गत ऊर्जा शुल्क वर्तमान में 650 पैसे (6.50 रुपये) प्रति यूनिट निर्धारित है। सभी लागू छूटों को ध्यान में रखते हुए, एचटी-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क 6.30 रुपये प्रति किलोवाट घंटा बनता है। डिस्कॉम ने एचटी-3 उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क को सभी छूटों के बाद 6.00 रुपये प्रति किलोवाट घंटा करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क दर 650 पैसे प्रति यूनिट पर अपरिवर्तित रहेगी। इस समायोजन का उद्देश्य मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करना और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी दरें उपलब्ध कराना है। इस संशोधन का उद्देश्य सामर्थ्य को बढ़ाना, राजस्थान में औद्योगिक विकास को समर्थन देना और डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता को बनाए रखते हुए बाजार की स्थितियों और आपूर्ति लागत के रुझानों के अनुरूप होना है।
2. सार्वजनिक सड़क प्रकाश व्यवस्था (पीएसएल) श्रेणी के लिए समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क (टीओडी) को हटाना:डिस्कॉम ने सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग (पीएसएल) उपभोक्ताओं के लिए टाइम-ऑफ-डे (टीओडी) टैरिफ को हटाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटें मुख्य रूप से शाम और रात के शुरुआती घंटों में, आमतौर पर सूर्यास्त से लेकर आधी रात या सुबह तक चलती हैं और ऑफ-पीक समय में लोड को स्थानांतरित नहीं कर सकतीं, जो कि टीओडी टैरिफ का मूल उद्देश्य है। इसलिए, ये उपभोक्ता न तो सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान लागू कम टैरिफ का लाभ उठा सकते हैं और न ही पीक-घंटे के सरचार्ज से बच सकते हैं, जिससे टीओडी का अनुप्रयोग अनुचित हो जाता है।
3. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ की शुरुआतविद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। उपरोक्त दिशानिर्देशों के खंड 9 में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ अनिवार्य किया गया है, जो 31.03.2028 तक आपूर्ति की औसत लागत (ACoS) पर सीमित है, जिसमें सौर ऊर्जा के घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान 0.7 गुना ACoS और गैर-सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान 1.3 गुना ACoS शुल्क लागू होगा। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप और राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, वितरण कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए मौजूदा निश्चित शुल्कों को हटाकर एकल-भाग टैरिफ पर स्थानांतरित होने का प्रस्ताव करती हैं।
4. बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्ताव:-डिस्कॉम्स ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा 17 में वर्तमान में कहा गया है कि जैसा कि नीचे दिया गया है:

"यदि एमडीआई द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग एक वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक 50 केवीए से अधिक हो जाती है, तो एलटी से एचटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में, उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष में तीसरी बार अधिकतम मांग से अधिक होने पर संबंधित सहायक अभियंता द्वारा जारी नोटिस की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर 11 केवी पर आपूर्ति लेनी होगी। अनुपालन न करने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाएगा।"

डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति टैरिफ की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें "दो बार से अधिक" वाक्यांश को "तीन बार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। वर्तमान शब्दावली अस्पष्ट है क्योंकि इसमें "दो बार से अधिक" का उल्लेख तो है, लेकिन तीसरी बार ऐसा होने पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। TCOS-2021 के खंड 4.8(b) में पहले से ही यह निर्दिष्ट है कि एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार निर्धारित सीमा से 5% से अधिक मांग होने पर टैरिफ में बदलाव लागू होगा। इसलिए डिस्कॉम ने प्रस्ताव दिया है कि परिभाषा 17 को TCOS के अनुरूप करने से स्पष्टता, एकरूपता सुनिश्चित होगी और व्याख्या संबंधी समस्याएं दूर होंगी।

5. 5 किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए गैर-घरेलू श्रेणी में स्लैबों का विलय।:याचिकाकर्ता का कहना है कि मौजूदा गैर-घरेलू (एनडीएस) टैरिफ संरचना जटिल है और इससे परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारदर्शिता बढ़ाने और टैरिफ के आवेदन को सरल बनाने के लिए, डिस्कॉम ने 200 यूनिट तक के गैर-घरेलू खपत स्लैब को एक ही स्लैब में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार, 5 किलोवाट तक के स्वीकृत लोड वाले एनडीएस उपभोक्ताओं के लिए, डिस्कॉम ने नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई संशोधित एकीकृत टैरिफ संरचना का प्रस्ताव दिया है।

गैर-घरेलू सेवा	मांग/निश्चित शुल्क (रु.)	ऊर्जा शुल्क (रु./यूनिट)
5 किलोवाट तक के एससीएल के लिए एनडीएस		
एनडीएस प्रकार 1		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	350	7.00
प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत।		8.50
एनडीएस प्रकार 2		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	450	7.00
प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत।		8.50
प्रति माह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक की खपत		
एनडीएस प्रकार 3		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	700	7.00
प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत।		8.50
प्रति माह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक की खपत		
प्रति माह 500 यूनिट से अधिक की खपत		

6. सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट श्रेणी के लिए निश्चित शुल्कों पर अधिकतम सीमा को पुनः लागू करना: डिस्कॉम्स ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट (पीएसएल) श्रेणी के लिए मौजूदा निश्चित शुल्क बहुत अधिक हैं। इस स्थिति से पीएसएल उपभोक्ताओं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नगर निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं के एक सेवा कनेक्शन से कई लैंप पॉइंट जुड़े होते हैं और इन उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क प्रति लैंप पॉइंट के आधार पर गणना की जाती है। इस प्रभाव को कम करने और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, डिस्कॉम्स पीएसएल श्रेणी के लिए प्रति सेवा कनेक्शन निश्चित शुल्क पर एक सीमा फिर से लागू करने का प्रस्ताव करते हैं। इस उपाय का उद्देश्य नगर निकायों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे डिस्कॉम की राजस्व आवश्यकताओं से समझौता किए बिना सार्वजनिक कल्याण उद्देश्यों का समर्थन किया जा सके। पीएसएल श्रेणी के लिए प्रस्तावित टैरिफ संरचना नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट	मांग/निश्चित शुल्क	ऊर्जा शुल्क (रुपये प्रति यूनिट)
जनसंख्या <1 लाख	प्रति लैंप पॉइंट 150 रुपये प्रति माह, प्रति सेवा कनेक्शन प्रति माह अधिकतम 3000 रुपये के अधीन।	7.00
जनसंख्या >1 लाख	प्रति लैंप पॉइंट 200 रुपये प्रति माह, प्रति सेवा कनेक्शन प्रति माह अधिकतम 8000 रुपये के अधीन।	7.50

टिप्पणी:- याचिका में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

अधिशाषी अभियंता (RA&C)
याचिकाकर्ता की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राज.संवाद/सी/25/15997

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर, वेबसाइट www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 64(2) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, अजमेर (डिस्कॉम द्वारा भी निर्दिष्ट) ने विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 62 और 64 सपठित रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनिश्चियन की निबन्धन व शर्ते) विनियम 2019 समयानुसार संशोधित, रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनिश्चियन की निबन्धन व शर्तें) विनियम 2025 तथा रा.वि.वि.आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम 2006 के अन्तर्गत विव. 2024-25 की समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग-अप, विव. 2026-27 के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दायर की है।

याचिका की प्रतियां निरीक्षण/अवलोकन के लिए और रू. 200/- के भुगतान पर विक्रय के लिए आयोग के कार्यालय और निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं :-

1. अनुज्ञप्तिधारी का मुख्यालय- विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर।
2. कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), अविविनिलिः- ब्लॉक-आई, हाथीभाटा पॉवर हाऊस, अजमेर-305001।
3. अधीक्षण अभियन्ता (पवस), अजमेर/ब्यावर/भीलवाडा/उदयपुर/सलुम्बर/झुंझुनू/नागौर/सीकर/चितौडगढ/बांसवाड़ा/राजसमन्द/डूंगरपुर/प्रतापगढ/डीडवाना-कुचामन स्थित कार्यालय।

याचिका **www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl** (अजमेर डिस्काम की वेबसाइट) और आरईआरसी की वेबसाईट **www.rerc.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इस याचिका का एक श्रव्य-दृश्य प्रदर्शन का आयोजन भी दिनांक 26.12.2025 (शुक्रवार) को सभागार, विद्युत भवन, पंचशील नगर, अजमेर में दोपहर 12 बजे रखा गया है। इच्छुक व्यक्ति नियत दिनांक व स्थान पर इस प्रदर्शन हेतु उपस्थित हो सकते है।

टिप्पणी/सुझाव भेजने के इच्छुक व्यक्ति सहायक प्रपत्रों और राविविआ (कार्य सम्पादन) विनियम 2021 के फार्म सं0 3 में शपथपत्र सहित प्राप्ति अधिकारी, राविविआ, विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर - 302001 के पते पर 6 प्रतियों में भेज सकते हैं जिससे कि ये प्राप्ति अधिकारी के पास दिनांक 09.01.2026 तक या उससे पूर्व पहुंच जायें।

विव. 2024-25 की समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग-अप, विव. 2026-27 के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका का संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है (याचिका संख्या 2379/2025):-

सारिणी 1 : विव. 2024-25 की समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रू अप का सारांश (करोड़ रू.)

क्र. सं.	विवरण	अजमेर डिस्कॉम स्वीकृत	अजमेर डिस्कॉम ट्रू अप के लिये किया गया दावा
1.	राजस्व		
2.	ऊर्जा विक्रय	21,496	20,926
3.	वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिये फ्यूल सरचार्ज की वसूली	1370	
4.	ट्रेडिंग द्वारा ऊर्जा विक्रय	0	128
5.	गैर टैरिफ और अन्य टैरिफ आय (आरवीपीएन/आरवीयूएन के ट्रू-अप केडिट सहित)	497	843
6.	विद्युत परिवहन, प्रति सहायिकी और अतिरिक्त अधिभार से आय	4	3
7.	कुल राजस्व (अ)	23,367	21,899
8.	व्यय		
9.	ऊर्जा क्रय लागत प्रसारण शुल्क सहित	15,616	15,451
10.	पवस व्यय	1582	1519
11.	सेवान्त लाभ	570	771
12.	ह्रास	701	1119
13.	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज सहित)	798	895
14.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	158	2024
15.	विनियामक संपत्तियों पर ब्याज	1489	
16.	अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो	0	(2)
17.	बीमा व्यय	30	1
18.	अन्य व्यय (उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट सहित)	315	228
19.	**कुल व्यय स.रा.आ. (ब)**	**21259**	**22006**
20.	**अधिशेष /(कमी) (स= अ-ब)**	**2108**	**(107)**
21.	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सब्सिडी/अनुदान		
22.	धारा 65 के तहत सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार से प्राप्त राजस्व सहायिकी (द)	18	0
23.	एफआरबीएम योजना के तहत् सब्सिडी (ई)	0	0
24.	सब्सिडी के बाद राजस्व अधिशेष/(कमी) (एफ=स+द+ई)	2126	(107)
25.	विलंबित भुगतान अधिभार (उपभोक्ताओं से) (जी)		134
26.	असाधारण आय/ (व्यय) (एच)		1982
27.	**कुल राजस्व अधिशेष/(अन्तर) ट्रूअप (एफ-जी+एच)**	**2126**	**1742**

सारिणी 2 : विव. 2026-27 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू. में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
1.	विद्युत क्रय व्यय	14464
2.	पवस व्यय	
2.1	कर्मचारी व्यय	1168
2.2	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय	200
2.3	मरम्मत एवं संधारण व्यय	530
2.4	सेवान्त लाभ	818
3	ह्रास	1663
4.	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज सहित)	1042
5.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	198
6.	नियामक सम्पत्ति पर ब्याज	813
7.	प्रसारण अधिभार	1830
8.	एन.एल.डी.सी./आर.एल.डी.सी./एस.एल.डी.सी. अधिभार	9
9.	अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो	-
10.	**कुल राजस्व आय**	**22736**
11.	साम्या पर प्रतिफल	-
12.	साम्या पर कर	-
13.	**समग्र राजस्व आवश्यकता**	**22736**
14.	घटायें - गैर टैरिफ आय	546
15.	घटायें- व्हीलिंग प्रभार से आय	3
16.	घटायें-क्रास सब्सिडी से प्राप्तियां	0
17.	घटायें- व्हीलिंग पर अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियां	0
18.	**खुदरा दरों से निवल समग्र राजस्व आवश्यकता (13-14-15-16-17)**	**22188**
19.	वर्तमान टैरिफ पर विद्युत विक्रय से आय	22198
20.	ट्रेडिंग गतिविधि से आय	194
21.	नियामक अधिभार से राजस्व	2461
22.	एफपीपीएएस से राजस्व	415
23.	पीओसी से राजस्व	45
24.	सरकार से सब्सिडी (हानि सहायिकी सहित)	0
25.	**मौजूदा टैरिफ पर वर्ष के लिये राजस्व अधिशेष/कमी (19+20+21+22+23+24-18)**	**3125**
26.	टैरिफ युक्तिकरण के बाद विद्युत की बिक्री से राजस्व	22194
27.	युक्तिकरण के बाद राजस्व में वृद्धि/(कमी)	(4)
28.	**टैरिफ युक्तिकरण के बाद वर्ष हेतु अधिशेष/(घाटा) (25+27)**	**3121**

सारिणी 3 : राज्य परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (एम.यू.)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
राज्य परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (एम.यू.)	33,419

सारिणी 4: वितरण हानि (%)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
वितरण हानियां (%)	7.50%

डिस्कॉम ने विव. 2026-27 के लिये निवेश योजना निम्नानुसार प्रस्तावित की है:-

सारिणी 5 - वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये निवेश योजना तथा निधियन के स्रोत (करोड़ रुपये)

क्र. सं.	योजना का नाम	राशि
1.	उप प्रसारण व वितरण	700
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	1520
3.	आरडीएसएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	700
4.	आरडीएसएस (आईटी/ओटी)	64
5.	आरडीएसएस (फीडर पृथक्करण)	2242
6.	आरडीएसएस (डीए-जेजीयूए)	21
	कुल	5248
क्र. सं.	निधियन के स्रोत	राशि
1.	ऋण	1414
2.	अनुदान	1828
3.	अंशपूंजी	1881
4.	उपभोक्ता योगदान	125
	कुल	5248

क्रॉस सब्सिडी अधिभार, व्हीलिंग प्रभार, अतिरिक्त अधिभार और ग्रीन पॉवर टैरिफ में बदलाव का प्रस्ताव भी डिस्कॉम ने निम्नानुसार दिया हैः-

सारिणी 6: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित क्रॉस सब्सिडी अधिभार

श्रेणी	वोल्टेज (केवी)	सीएसएस (रू. प्रति यूनिट)
वृहद श्रेणी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
मिश्रित भार - एचटी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
अघरेलू - एचटी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75

सारिणी 7 : वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित व्हीलिंग प्रभार (रू. प्रति यूनिट)

विवरण	रू. प्रति यूनिट
132 केवी पर व्हीलिंग प्रभार	0.01
33 केवी पर व्हीलिंग प्रभार	0.11
11 केवी पर व्हीलिंग प्रभार	0.63
एलटी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग प्रभार	2.49

सारणी 8- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार (रू. प्रति यूनिट)

विवरण	रू. प्रति यूनिट
अतिरिक्त अधिभार	0.47

सारिणी 9 : वित वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित ग्रीन पॉवर टैरिफ

विवरण	(रू. प्रति यूनिट)
ग्रीन पॉवर टैरिफ	0.00*

* नोटः- डिस्कॉम ने उन उपभोक्ताओं से कोई प्रीमियम चार्ज नहीं लेने का प्रस्ताव दिया है जो डिस्कॉम से ग्रीन पावर लेना चाहते हैं। ग्रीन पावर उसी रेट पर दी जायेगी जो किसी सम्बन्धित श्रेणी के लिये लागू है।

डिस्कॉम ने याचिका में किसी टैरिफ संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि, डिस्कॉम ने निम्नलिखित टैरिफ युक्तिकरण उपायों की मांग की हैः-

1. मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एम.पी./एचटी-3) के लिये न्यूनतम ऊर्जा शुल्क में कमी:-

अनुसूची एम.पी./एचटी-3 मध्यम औद्योगिक सेवा के तहत् ऊर्जा शुल्क वर्तमान में रूपये 6.50 प्रति यूनिट निर्धारित हैं। सभी लागू छूटों को शामिल करने के बाद, एचटी-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम ऊर्जा शुल्क रूपये 6.30 प्रति यूनिट निर्धारित होता है। डिस्कॉम प्रस्तावित करता है कि एचटी-3 उपभोक्ताओं के लिये सभी छूटों के बाद न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क को 6.00 रूपये प्रतियूनिट तक संशोधित किया जाए, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क दर को 6.50 रूपये प्रति यूनिट पर अपरिवर्तित रखा जाए। इस समायोजन का उद्देश्य मध्यम औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस संशोधन का लक्ष्य राज्य में सामर्थ्य बढ़ाने और औद्योगिक विकास को समर्थन मिलने हेतु निर्धारित किया है। यह संशोधन प्रचलित बाजार स्थितियों और आपूर्ति प्रवृत्तियों की लागत तथा याची की वित्तीय व्यवहार्यता की सुनिश्चितता को ध्यान में रख किया है।

2. सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग (पीएसएल) श्रेणी के लिये टॉइम-ऑफ-डे (टीओडी) टैरिफ हटानाः-

डिस्कॉम सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग उपभोक्ता श्रेणी के लिये टॉइम-ऑफ-डे (टीओडी) टैरिफ की प्रयोजकता को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग स्थापनाएँ मुख्य रूप से शाम और रात के शुरूआती घंटों में, आम तौर पर सूर्यास्त से लेकर मध्यरात्रि या सुबह जल्दी तक होती है और लोड को ऑफ-पीक समय में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, जो टीओडी टैरिफ का मुख्य हिस्सा है। इसलिये, इन उपभोक्ताओं को न तो सोलर घंटों के दौरान लागू कम टैरिफ का फायदा मिलेगा और न ही वे पीक आवर सरचार्ज से बच पायेंगे, जिससे टीओडी एप्लीकेशन पीएसएल श्रेणी के लिये असमान हो जायेगी।

3. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिये सिंगल-पार्ट टैरिफ की शुरुआतः-

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिये दिशा-निर्देश 2024 जारी किये है। इन दिशा-निर्देशों का बंध 9 की गाइडलाइंस में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिये सिंगल पार्ट टैरिफ जो कि 31.03.2028 तक सप्लाई की औसत आपूर्ति लागत यथा सोलर घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान 0.7xऔसत आपूर्ति लागत और नॉन-सोलर घंटों के दौरान 1.3xऔसत आपूर्ति लागत पर कैप होगा, की अनिवार्यता की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान में ईवी चार्जिंग स्टेषनों को बढ़ावा देने के लिये, डिस्कॉम ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर लागू मौजूदा स्थायी शुल्कों को हटाकर एकल-भार टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव करता है।

4. विद्युत आपूर्ति के लिये टैरिफ-2025 की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्तावः

विद्युत आपूर्ति के लिये टैरिफ-2025 की परिभाषा 17 वर्तमान में यह वर्णित करता हैः-

अधिकतम मांग सूचक (एम डी आई) के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में दो से अधिक बार अधिकतम मांग 50 केवीए से अधिक पाये जाने पर एलटी से एचटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में, किसी वित्तीय वर्ष में तीसरी बार मांग 50 केवीए से अधिक होने पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता को नोटिस दिए जाने के दो माह की अवधि के अन्दर-अन्दर 11 के.वी. पर आपूर्ति लेनी होगी, जिसमें विफल होने पर उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा।

डिस्कॉम ने विद्युत आपूर्ति के टैरिफ के नियम 17 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ''दो से ज्यादा'' वाक्यांश को 'तीन' से बदला जाए। मौजूदा शब्दों में अस्पष्टता है इसमें 'दो से ज्यादा बार' का जिक्र है, जबकि तीसरे बार होने पर कार्रवाई की जरूरत है। टीसीओएस-2021 का बंध 4.8(b) निर्दिष्ट करता है कि अगर एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार अधिकतम डिमाण्ड 5 प्रतिशत से ज्यादा हो जाती है, तो चेंज ओवर लागू होगा। इसलिये डिस्कॉम ने प्रस्ताव दिया है कि परिभाषा 17 को टीसीओएस के साथ मिलाने से स्पष्टता, निरंतरता सुनिश्चित होगी और व्याख्या संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी।

5. 5 किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ताओं के लिये गैर-घरेलू श्रेणी में स्लैब का विलयः

याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिये मौजूदा टैरिफ संरचना में कुछ जटिलताएँ है, जिससे परिचालन संबंधी चुनौतियाँ और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारदर्शिता और सरल टैरिफ अनुप्रयोग कों बढ़ावा देने के लिये, डिस्कॉम 200 यूनिट तक की खपत के लिये गैर-घरेलू स्लैब को एक एकल स्लैब में विलय करने का प्रस्ताव करता है। डिस्कॉम द्वारा 5 किलोवाट तक की स्वीकृत संबंद्ध भार वाले एनडीएस श्रेणी के लिये संशोधित टैरिफ संरचना प्रस्तावित है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में अंकित हैं:

अघरेलू सेवा	संविदा/स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)
अघरेलू 5 किवा तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार		
अघरेलू प्रकार-1		
प्रतिमाह पहले 100 यूनिट तक उपभोग	350	7.00
प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक उपभोग		8.50
अघरेलू प्रकार-2		
प्रतिमाह पहले 100 यूनिट तक उपभोग	450	7.00
प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक उपभोग		8.50
प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक उपभोग		
अघरेलू प्रकार-3		
प्रतिमाह पहले 100 यूनिट तक उपभोग	700	7.00
प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक उपभोग		8.50
प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक उपभोग		
प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक तक उपभोग		

6. सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग (पीएसएल) श्रेणी के लिये स्थाई प्रभार पर अधिकतम सीमा की पुनः शुरूआतः

डिस्कॉम प्रस्तुत करता है कि विव 2025-26 के टैरिफ आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग श्रेणी के लिये मौजूदा स्थाई प्रभार बहुत ज्यादा हो गया हैं। यह स्थिति पीएसएल उपभोक्ताओं, विशेष रूप से नगर पालिकाओं और सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग व्यवस्था के लिये जिम्मेदार स्थानीय प्राधिकरणों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ऐसे उपभोक्ताओं के पास एक सेवा कनेक्शन से जुड़े कई लैंप पॉइंट होते हैं तथा ऐसे उपभोक्ताओं के लिये स्थाई प्रभार प्रति लैंप पॉइंट के आधार पर परिकल्पित किये जाते है। इस प्रभाव को कम करने और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिये, डिस्कॉम्स सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग श्रेणी के लिये सेवा कनेक्शन स्थाई प्रभार पर अधिकतम सीमा को पुनः लागू करने का प्रस्ताव रखता हैं। इस उपाय का उद्देश्य डिस्कॉम के राजस्व की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना नगर निकायों के लिये वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों को समर्थन मिल सकें।

पीएसएल श्रेणी के लिये प्रस्तावित टैरिफ संरचना निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई हैं:

सार्वजनिक स्ट्रीट लाईट	संविदा/स्थाई प्रभार	विद्युत प्रभार (रू. प्रति यूनिट)
जनसंख्या एक लाख से कम	3000/- रू. प्रति सेवा कनेक्शन प्रतिमाह के अधिकतम के अध्यधीन 150 रूपये प्रति लैम्प बिन्दु प्रतिमाह	7.00
जनसंख्या एक लाख या एक लाख से अधिक	8000/- रू. प्रति सेवा कनेक्शन प्रतिमाह के अधिकतम के अध्यधीन 200 रूपये प्रति लैम्प बिन्दु प्रतिमाह	7.50

नोट :- 1. विस्तृत विवरण याचिका में उपलब्ध है।

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)
याचिकाकर्ता के निमित्त अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राज.संवाद/सी/25/15937

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने आहोर में जालोर जिले के 338 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया।

जालोर/जयपुर, 17 दिसम्बर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद करते हुए भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता सहित, विभिन्न प्रकरणों में निलंबित किया गया है तथा 34 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है।

शर्मा बुधवार को आहोर (जालोर) में ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण व शहरी समस्या समाधान शिविर में लोकतंत्र सैनानियों से मुलाकात की व दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे विलेख, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना सहित विभिन्न योजनाओं के चैक वितरित किए।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को आहोर में जालोर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र व चेक वितरित किए।

शिविर तथा जालोर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज जालोर में 338 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख 18 हजार किसानों के खेतों में 10 हजार 432 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी गई है।

आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा जालोर और आहोर विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को रेखांकित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सैनानियों से मुलाकात और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने ग्रामीण और शहरी शिविरों का अवलोकन किया और लाभार्थियों को पट्टे विलेख, गोपाल क्रेडिट योजना सहित, विभिन्न योजनाओं के चेक वितरित किए।

कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, विधायक जीवाराम चौधरी सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

एच वन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

10,400 से ज्यादा कर्मचारियों की थीं, पर 1,00,000 डॉलर की फीस लगती, जिसमें वीज़ा शुल्क के रूप में कुल रकम एक अरब डॉलर से भी अधिक हो गई होती।

टाटा को इस अवधि में 6,500 कर्मचारियों के लिए फीस देनी पड़ती, जो नए स्वीकृत एच-1बी कर्मचारियों का 82 प्रतिशत है। वहीं कॉग्निज़ेंट को 5,600 से अधिक कर्मचारियों, यानी 89 प्रतिशत नई एच-1बी नियुक्तियों के लिए यह शुल्क चुकाना पड़ता। भले ही कानूनी चुनौतियों के जरिए इस शुल्क को जल्दी रोक दिया जाए, लेकिन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वीज़ा की मांग में भारी गिरावट आएगी और अधिक कर्मचारियों को विदेशों में ही तैनात किया जाएगा।

इमिग्रेशन वकील जोनाथन वासडेन, जो कई आईटी नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा, हम पहले से ही ऐसा होते देख रहे हैं। डर यह है कि अगर विदेशों में वास्तव में असाधारण प्रतिभा हैं, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अवसर से वंचित रह जाएंगे।

'अरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थरूर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव भी डाला। मनीष तिवारी भी इस समय खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी उनका उचित स्थान नहीं मिल रहा था, लेकिन उनका एसआईआर पर पहला भाषण आंखें खोलने वाला और सराहनीय प्रयास था, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के रूप में देखा गया।

अब तक राहुल गांधी का रुख यही था कि "अगर पार्टी छोड़नी है, तो आप यह करने के लिए स्वतंत्र हैं", लेकिन लगता है कि हाल के समय में उनका रुख बदल गया है।

'दिल्ली में अब बीएस-4 या उससे अधिक स्टैंडर्ड के वाहन ही चलेंगे'

दिल्ली में प्रदूषण में कटौती करने के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया

नयी दिल्ली,17 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली में केवल ऐसे वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी, जो बीएस-4 उत्सर्जन मानक या उससे ऊपर की श्रेणी के हैं।

न्यायालय के इस नए स्पष्टीकरण के बाद अब अधिकारी उन पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे, जो बीएस-चार मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वहीं, बीएस-4 या नये वाहनों को उनकी समय सीमा पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति है।

- **इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दस साल पुराने डीज़ल वाहनों व 15 साल पुराने पैट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी।**

न्यायालय का यह नवीनतम आदेश, उसके गत 12 अगस्त के उस पिछले आदेश में संशोधन करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर यह स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी गई थी।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच संवाद का उद्देश्य आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक पहलों को सशक्त करना बताया गया।

दिल्ली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी कहा गया है कि ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के तहत काम बंद होने के कारण प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देगी। नये जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राहुल गांधी व सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्वामी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दायर की गई एक निजी शिकायत पर आधारित था, न कि एफआईआर पर।

इसे गांधी परिवार के लिए एक तरह से "राहत" माना गया, लेकिन भाजपा के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीया ने इसे "भ्रामक हैडलाइन और दावा" करार दिया, क्योंकि इसमें "कोई राहत नहीं थी।"

- **जैसा कि विदित ही है, न्यायालय के निर्णय के अनुसार, ईडी ने केवल एक व्यक्ति, सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर नैशनल हैरल्ड के मामले में मनी लॉण्डरिंग की जाँच शुरु कर दी थी, यह गैर कानूनी है, क्योंकि पहले एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद ही मनी लॉण्डरिंग कानून के तहत जाँच हो सकती है।**

मालवीया के अनुसार, अदालत ने "कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यु) ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए ईडी नए सिरे से केस को आगे बढ़ा सकता है। एफआईआर के कारण ईडी की दलीलें पीएमएलए के तहत वैध और प्रक्रियागत रूप से मान्य हो जाती हैं।"

उन्होंने कहा, "असल में, अदालत ने ईडी की चार्ज शीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि इसमें प्रक्रिया संबंधी गलतियां थीं, जिनमें पीएमएलए के तहत निर्धारित एफआईआर का नहीं होना भी शामिल था। भाजपा नेता यह तर्क कर रहे हैं। यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि गांधी परिवार और उनके सहयोगियों ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग करके एजेएल (नेशनल हैरल्ड का प्रकाशक) पर नियंत्रण प्राप्त किया था, और इसमें 90 करोड़ रुपये के ऋणों का हेरफेर भी शामिल था।

'भारत का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और पार्टी की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी।

यह पांच दिवसीय दौरा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान घोषित किया गया था, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने इसकी व्यापक आलोचना की थी। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की बार-बार की विदेश यात्राएं कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके समर्पण पर सवाल उठाती हैं।

'हम सैवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रैली में यह बात कही, "सेवन सिस्टर्स भारत से अलग कर दी जाएगी।" यह रैली उन लोगों के खिलाफ आयोजित की गई थी, जो एक अन्य छात्र नेता, उस्मान हादी के हमले में शामिल थे, और यह दावा किया जा रहा था कि आरोपियों को भारत से समर्थन मिल रहा है। अब्दुल्ला द्वारा की गई यह उत्तेजक टिप्पणी उस समय आई, जब बाँग्लादेश इस सप्ताह के शुरु में अपना 55वां विजय दिवस मना रहा था। इस बीच, भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है तथा विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, "हम उम्मीद करते हैं कि बांगलादेश की अंतरिम सरकार आंतरिक कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी, जिससे शांतिपूर्ण चुनावों के आयोजन का उद्देश्य भी पूरा हो सके।

'सबका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थानांतरण के लिए पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होगी। पहले यह सीमा एक प्रतिशत थी। सभी बीमा कंपनियों और बिचौलियों के लिए अपने नाम में "बीमा" शब्द रखना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908